अंतरराष्ट्रीय व्यापार

7
अध्याय

जैसे ही वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के आघात से दबी-पिसी विश्व-अर्थव्यस्था और व्यापार ने उबरना शुरू किया तथा अनेक विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थों में उत्पादन एवं व्यापार संकट-पूर्व के स्तरों तक पहुंचने लगा, बल्कि संकट-पूर्व के रूझानों से भी आगे बढ़ने लगा, तभी यूरो क्षेत्र में आए संकट और अमरीका में छाई मन्दी के रूप में दूसरा झटका लगा। यूरो क्षेत्र में व्याप्त संरचनागत ऋण संकट और अमरीका में छाया राजकोषीय असन्तुलन, जिसकी वजह से मौजूदा संकट पैदा हुआ है, पूर्ववर्ती संकट से उपजे थे। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में हो रही गिरावट के मुकाबले विश्व-व्यापार में आई कमी अधिक तीव्र होने के चलते 2008-2009 के खलबली से भरपूर, मन्दी से ग्रस्त वर्ष वापस लौटते प्रतीत हो रहे हैं। भारत के निर्यात, जो न सिर्फ संकट-पूर्व के स्तरों से अधिक हो गए थे, बल्कि संकट-पूर्व रूझानों से भी आगे बढ़ गए थे, अब इस दूसरी वैश्विक मंदी की गरमी महसूस कर रहे हैं, जो पहले संकट के एकदम बाद ही प्रकट हो गई, हालांकि संकट का सामना करने के लिए हमारा देश कई अन्य देशों की बनिस्बत बेहतर स्थिति में है।

विश्व व्यापार

7.2 विश्व व्यापार का मूल्य जो वर्ष 2008 के 16 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर से तेज़ी से कम होकर 2009 में 12.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर रह गया, थोड़ा बेहतर होकर 2010 में 15.1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर आ गया, हालांकि यह संकट-पूर्व के स्तर से अभी भी कम था। विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि में भी तेज़ी आई जो वर्ष 2009 के -10.7 प्रतिशत की ऋणात्मक स्थिति से बेहतर होकर 2010 में 12.7 प्रतिशत हो गया, हालांकि यह भी संकट-पूर्व की वृद्धि से कम था। कम आधार वाला पूर्ववर्ती प्रभाव न होने के चलते यह कम होकर 2011 में 6.9 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 7.1)।

7.3 वर्ष 2011 के पूर्वार्ध में, विश्व व्यापार 23.1 प्रतिशत की मूल्य-वृद्धि के साथ 8.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर आ गया था। लेकिन यूरो क्षेत्र के बढ़ते संकट के 2011 की चौथी

सारणी 7.1 : व्यापार मात्रा में वृद्धि संबंधी रूझान

(प्रतिशत में परिवर्तन)

			अनुमान		सितं. 2011 के डब्ल्यूईओ अनुमानों में अन्तर	
	2010	2011	2012	2013	2012	2013
विश्व व्यापार की मात्रा (माल एवं सेवाएं)	**12.7**	**6.9**	**3.8**	**5.4**	**-2.0**	**-1.0**
आयात						
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	11.5	4.8	2.0	3.9	-2.0	-0.8
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	15.0	11.3	7.1	7.7	-1.0	-1.0
निर्यात						
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	12.2	5.5	2.4	4.7	-2.8	-0.8
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	13.8	9.0	6.1	7.0	-1.7	-1.6

स्रोत: आईएमएफ; डब्ल्यू ई ओ, जनवरी 2012

तिमाही में नए खतरनाक दौर में दाखिल होने के चलते, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, जनवरी 2012 के अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा में होने वाली वृद्धि धीमी होकर 2012 में 3.8 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। वर्ष 2012 में व्यापार-वृद्धि का लगभग आधा हो जाना वर्ष 2008 की ही तरह आसन्न संकट का अशुभ संकेत है।

7.4 आईएमएफ द्वारा विश्व उत्पादन के वृद्धि संबंधी अनुमानों को कम करके 2012 में 3.3 प्रतिशत और 2013 में 3.9 प्रतिशत पर लाने के चलते तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास सीमित नीतिगत विकल्पों की वजह से इन अर्थव्यवस्थाओं के 2012 में 1.2 प्रतिशत पर विकसित होने की संभावना है। यह 2.0 और 2.4 प्रतिशत के स्तर पर उनके क्रमश: आयात एवं निर्यात व्यापार की संभावित मात्रा में भी प्रतिबिंबित होती है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 2012 में 5.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत बेहतर दर पर विकास करने की संभावना है, जहां आयात एवं निर्यात की मात्रा में क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी। (सारणी 7.1)

व्यापार ऋण

7.5 व्यापार ऋण की उपलब्धता और लागत दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण पैमाना है। हालिया वर्षों में इस मोर्चे पर कई उतार-चढ़ाव हुए हैं।

व्यापार ऋण: अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

7.6 अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) द्वारा सितंबर 2011 के उत्तरार्ध में किए गए नवीनतम त्रैमासिक सर्वेक्षण के अनुसार, उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में स्थित बैंक बैंक-उधारों की अपेक्षाकृत सख्त स्थितियां झेल रहे थे। बैंक-उधारों की स्थितियों का समग्र सूचकांक 2011 की तीसरी तिमाही में अपने अब तक के क्षीणतम स्तर तक जा पहुंचा। इस तरह, 2011 की तीन तिमाहियों में उभरते बाज़ारों में बैंक-उधार की स्थितियों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है और इस दौरान समग्र सूचकांक अपने सबसे मज़बूत स्तर से हटता हुआ अपने सबसे कमज़ोर स्तर तक आ पहुंचा है। सबसे उल्लेखनीय गिरावट उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों द्वारा झेली जा रही निधिपोषण संबंधी स्थितियों में आई है। हालांकि स्थानीय निधिपोषण की स्थितियां तीसरी तिमाही में कुल मिलाकर अपरिवर्तित रहीं, अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में निधिपोषण की स्थितियां बहुत खराब हुई हैं और ऐसा सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है। ऐसे स्पष्ट प्रमाण हैं कि परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती समस्याएं उभरते बाज़ारों में असर दिखा रही हैं–खासतौर पर यूरो क्षेत्र में व्याप्त गंभीर ऋण समस्याओं से उभरने वाली चुनौतियां।

7.7 अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण की स्थितियों पर मौजूदा अस्थिर वित्तीय स्थितियों का भी बुरा असर पड़ा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण की स्थितियों का समग्र प्रसार सूचकांक अभी भी 50 के आरंभिक स्तर से लगभग ऊपर है (यूरोप के लिए यह रीडिंग 49.3 है), लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले भाव अभी मन्द है। (50 से ऊपर प्रसार सूचकांक का अर्थ है अधिक शक्ति, 50 से कम का अर्थ है कमज़ोरी और 50 तटस्थ रीडिंग है)। 2011 की तीसरी तिमाही में, 23 प्रतिशत बैंकों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण की स्थितियों में सुधार हो गया है, जबकि 2011 की दूसरी तिमाही में यह 44 प्रतिशत था। सर्वाधिक मज़बूत सुधार एशिया में देखा गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण की मांग यूरोप में मामूली सी कम हुई है, जबकि यह अन्य क्षेत्रों में ज़बरदस्त बनी रही। यूरोप में, 17 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि पिछली तीन तिमाहियों में मांग में कमी आई है। आपूर्ति के मोर्चे पर, लैटिन अमरीका में स्थित बैंकों ने व्यापार वित्तपोषण करने की इच्छा में कमी होने की खबर दी, जबकि अफ्रीका और मध्य-पूर्व (एएफएमई) तथा एशिया में आपूर्ति की स्थितियों में सुधार होना जारी रहा। समग्र रूप से, 19 प्रतिशत बैंकों ने आपूर्ति की स्थितियों में सुधार को स्वीकृत किया (2011 की दूसरी तिमाही में 42 प्रतिशत की तुलना में)।

व्यापार ऋण: भारतीय परिदृश्य

7.8 वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सुधार को प्रतिबिंबित करते हुए, भारत को मिलने वाले अल्पावधिक व्यापार ऋण का सकल प्रवाह 2010-11 के दौरान 75.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया, जो 2009-10 के दौरान दर्ज प्रवाह से 42.2 प्रतिशत अधिक था। 50.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर व्यापार ऋण 2011-12 के पूर्वार्ध में बढ़ोतरी का रुख़ दर्शाता रहा और इसमें 2010-11 के पूर्वार्ध के 59.8 प्रतिशत की तुलना में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, व्यापार ऋण के कारण बहिर्वाह में हुई वृद्धि 2010-11 के पूर्वार्ध के 28.1 प्रतिशत के मुकाबले 2011-12 के पूर्वार्ध में 57.7 प्रतिशत के स्तर पर अधिक थी। परिणामत: निवल अंतर्वाह 2010-11 के पूर्वार्ध के 6.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2011-12 के पूर्वार्ध में 5.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर मामूली सा कम था।

7.9 निर्यात ऋण वृद्धि पूरे वित्त वर्ष 2010-11 में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2011-12 (30 दिसंबर 2011 तक) में मार्चान्त 2011 के स्तर से कम होती हुई 8.4 प्रतिशत रह गई है। निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण में पिछले कई वर्षों में कमी होती रही है और यह 1999-2000 के 9.8 प्रतिशत के मुकाबले अप्रैल 2011 से 30 दिसंबर 2011 के दौरान केवल 4.2 प्रतिशत थी (देखें सारणी 7.2)।

7.10 चूंकि यूरो क्षेत्र में व्याप्त संकट से संबंधित मुद्दे सितंबर 2011 से गंभीर हो गए हैं, आगामी तिमाहियों में व्यापार ऋण में कमी होने का जोखिम बढ़ गया प्रतीत होता है। नकदी की सख्त स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में हालिया घटनाक्रम के कारण ऋण-विस्तार के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए, 15 नवंबर

सारणी 7.2 : निर्यात ऋण

निम्नलिखित तिथि को बकाया	निर्यात ऋण	अंतर (प्रतिशत)	एनबीसी के प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण
24 मार्च 2000	39118	9.0	9.8
22 मार्च 2002	42978	-0.8	8.0
21 मार्च 2003	49202	14.5	7.4
19 मार्च 2004	57687	17.2	7.6
18 मार्च 2005	69059	19.7	6.3
31 मार्च 2006	86207	24.8	5.7
30 मार्च 2007	104926	21.7	5.4
28 मार्च 2008	129983	23.9	5.5
27 मार्च 2009	128940	-0.8	4.6
26 मार्च 2010	138143	7.1	4.3
25 मार्च 2011	168841	22.2	4.3
30 दिसंबर2011	183004	8.4*	4.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

टप्पणी: *25 मार्च 2011 आंकड़ा की तुलना में घट-बढ़

*** ये आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर आरबीआई से निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्राप्त करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है।**

2011 को बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर उच्चतम सीमा को तत्काल और 31 मार्च 2012 तक लिबोर जमा 200 आधार बिन्दु की पूर्ववर्ती उच्चतम दर से बढ़ाकर लंदन अंतर बैंक पेशकश दर (लिबोर) जमा 350 आधार बिन्दु कर दिया गया, जो इस स्पष्ट शर्त के अध्यधीन होगी कि बैंक जेब से किए गए व्यय की वसूली को छोड़कर सेवा प्रभार और प्रबंधन प्रभार जैसे कोई अन्य प्रभार नहीं लगाएंगे। ऐसे मामलों में ब्याज दरों में परिवर्तन किए गए जहां बेंचमार्क के तौर पर यूरो लिबोर/यूरीबोर इस्तेमाल की गई है। विदेशी बैंकों की ऋण-श्रृखंलाओं पर उच्चतम ब्याज दर भी छः माह लिबोर/यूरी लिबोर/यूरीबोर जमा 100 आधार बिन्दु से बढ़ाकर लिबोर/यूरी लिबोर/यूरीबोर जमा 250 आधार बिन्दु कर दी गई है। ये परिवर्तन 31 मार्च 2012 तक लागू हैं और उसके बाद उनकी समीक्षा की जाएगी इसी प्रकार, इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि घरेलू आयातक मौजूदा ऑल-इन-कॉस्ट (एआईसी) की उच्चतम सीमा के अन्दर रहते हुए व्यापार ऋण जुटाने में कठिनाइयां अनुभव कर रहे थे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 नवम्बर, 2011 को एक वर्ष के व्यापार ऋण के साथ-साथ एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के व्यापार ऋणों के लिए एआईसी की उच्चतम सीमा को छः माह लिबोर जमा 200 आधार बिन्दु से बढ़ाकर लिबोर जमा 350 आधार बिन्दु कर दिया है। एआईसी की उच्चतम सीमा में व्यवस्थात्मक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, संचालन/प्रक्रियान्वयन प्रभार, जेबी और कानून खर्च, यदि कोई हो, शामिल हैं, एआईसी की उच्चतम सीमा भी 31 मार्च 2012 तक लागू है और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी।

भारत का पण्य व्यापार

7.11 भारत के निर्यात और आयात में पिछले दशक में पांच से सात गुना वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000-01 में क्रमशः 44.6 बिलियन अमरीकी डालर और 50.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़ते हुए वर्ष 2010 में क्रमशः 251.1 बिलियन अमरीकी डालर और 369.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। जहां 1990 के दशक में भारत के निर्यात और आयात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरें (सीएजीआर) (अमरीकी डालर में) क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत थी, वे 2000-01 से 2008-09 के दौरान बढ़कर क्रमशः 19.5 प्रतिशत और 25.1 प्रतिशत हो गई। भारत के व्यापार की समुत्थानशीलता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि इसकी निर्यात

सारणी 7.3 : व्यापार निष्पादनः मूल्य मात्रा एवं यूनिट मूल्य और आयात-निर्यात स्थिति में वृद्धि

(वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)

	निर्यात				आयात				आयात-निर्यात स्थिति	
	मूल्य				मूल्य					
	रुपए में	अमरीकी डालर में	परिमाण	यूनिट मूल्य	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य	निवल	आय
2001-02	2.7	-1.6	0.8	1.0	6.2	1.7	4.0	2.8	-2.1	-1.3
2002-03	22.1	20.3	19.0	2.9	21.2	19.4	5.8	14.3	-9.8	7.4
2003-04	15.0	21.1	7.3	7.5	20.8	27.3	17.4	3.1	3.6	11.2
2004-05	27.9	30.8	11.2	14.9	39.5	42.7	17.2	18.9	-3.5	7.3
2005-06	21.6	23.4	15.1	6.1	31.8	33.8	16.0	14.0	-6.0	8.2
2006-07	25.3	22.6	10.2	13.7	27.3	24.5	9.8	15.1	-1.3	8.8
2007-08	14.7	29.0	7.9	5.1	20.4	35.5	14.1	1.9	2.6	10.7
2008-09	28.2	13.6	9.0	16.9	35.8	20.7	20.2	13.8	2.5	11.7
2009-10	0.6	-3.5	-1.1	1.0	-0.8	-5.0	9.9	-10.0	12.3	11.1
2010-11	35.1	40.5	43.2	-5.1	23.4	28.2	10.1	11.2	-14.3	22.7
2011-12[क]							-	-	-	-

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डीजीसीआईएण्डएस) कोलकाता के आंकड़ों से संगणित

[क]: अप्रैल-दिसम्बर 2011

निर्यात एवं आयात की मात्रा एवं यूनिट मूल्य सूचकांक नए आधार (1999-2000=100) के साथ हैं।

चित्र 7.1 भारत के निर्यात की मासिक प्रवृत्तियां–मूल्य और वृद्धि

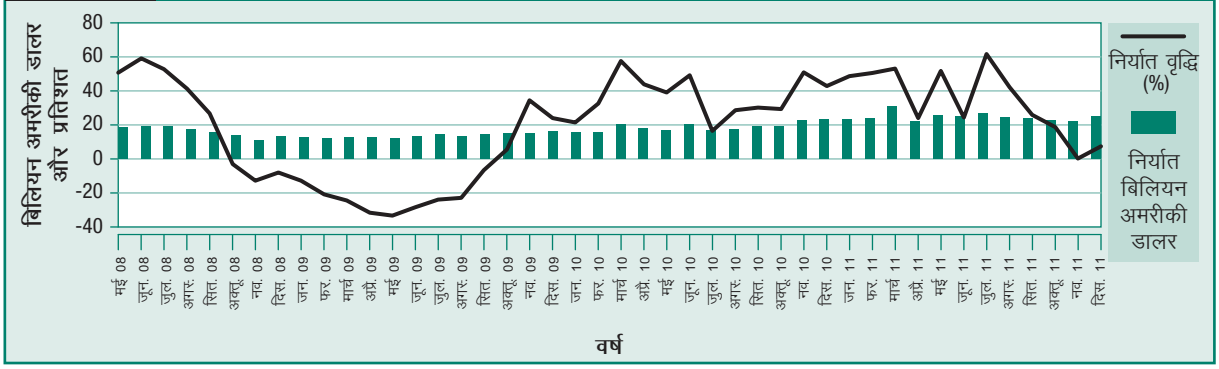

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस और आरबीआई के आंकड़ों पर आधारित।

और आयात-वृद्धि जो वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से मिले झटके के परिणामस्वरूप गिरकर 2009-10 में क्रमशः-3.5 प्रतिशत और -5 प्रतिशत हो गई थी, 2010-11 में पुनः सुधरकर क्रमशः 40.5 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत हो गई (सारणी 7.3)। अन्य कई विकासशील और यहां तक कि विकसित देशों के विपरीत भारत निर्यात में न सिर्फ संकट-पूर्व के स्तरों तक पहुंच गया, बल्कि निर्यात वृद्धि दर में संकट-पूर्व के रूझानों भी आगे निकल गया (चित्र 7.1)। वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 के क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 1.5 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत हो गया (डब्ल्यूटीओ के अनुसार 1.4 और 2.1 प्रतिशत)। अग्रणी निर्यातकों और आयातकों में इसका दर्जा वर्ष 2000 के क्रमशः 31 और 26 से बेहतर होकर वर्ष 2010 में क्रमशः 20 और 13 हो गया।

7.12 वर्ष 2011-12 के पूर्वार्ध के दौरान, भारत के निर्यात-क्षेत्र में 40.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि देखी गई। तथापि, यूरो क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में उभरे संकट और उसके केंद्रीय अर्थव्यवस्थाओं में फैलने, जिससे अब यूरो क्षेत्र में थोड़ी मन्दी की स्थिति दिखाई दे रही है, के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 2011 से निर्यात वृद्धि में कमी आई है।

7.13 निर्यातों में जुलाई 2011 में 61.1 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद इस वृद्धि में गिरावट हुई और यह गिरकर अगस्त, सितंबर और अक्तूबर 2011 में क्रमशः 41.5 प्रतिशत, 25.2 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत रह गई। नवंबर 2011 में निर्यात वृद्धि -0.5 प्रतिशत पर ऋणात्मक थी लेकिन दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में यह में धनात्मक थी लेकिन 6.7 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत के स्तर पर कम ज़रूर थी। संचयी निर्यात 242.8 बिलियन अमरीकी डालर के रहे और इनमें 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान, जिन निर्यात क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वे हैं-पेट्रोलियम और तेल उत्पाद जिनमें 55 प्रतिशत; रत्न एवं आभूषण में 38.5 प्रतिशत; इंजीनियरी में 21.6 प्रतिशत; सूती कपड़े के उत्पादों में 13 प्रतिशत; इलैक्ट्रानिक्स में 21.1 प्रतिशत; तैयार परिधानों में 23.7 प्रतिशत तथा औषधि में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

7.14 हालांकि डॉलर मूल्य में निर्यात वृद्धि 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 2010-11 की तदनुरूप अवधि की तुलना में थोड़ी कम हुई, फिर भी यह इसी अवधि में रुपये मूल्य में स्थिर थी या इसमें कम गिरावट हुई जो 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 3.1 प्रतिशत की गिरावट को प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबिंबित करती है। दूसरी ओर, रुपये मूल्य में आयात वृद्धि डॉलर मूल्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ी (चित्र 7.2 और 7.3)।

चित्र 7.2 निर्यात वृद्धि और विनिमय दर में घट-बढ़

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस और आरबीआई के आंकड़ों पर आधारित।

चित्र 7.3 आयात वृद्धि और विनिमय दर में घट–बढ़

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस और आरबीआई के आंकड़ों पर आधारित।

7.15 वर्ष 2010–11 में रुपये मूल्य में निर्यात वृद्धि में 35.1 प्रतिशत का सुधार यूनिट मूल्य सूचकांक की वृद्धि में कमी आने के बावजूद मुख्यत: मात्रा की वृद्धि में हुए बड़े सुधार (43.2 प्रतिशत) के कारण था। मात्रा के संदर्भ में निर्यातों में हुई अधिक वृद्धि सकारात्मक लक्षण है और यह मुख्यत: मशीनरी और परिवहन उपस्कर (85.1 प्रतिशत) मूलत: सामग्रियों के रूप में वर्गीकृत विनिर्मित वस्तुओं (41.2 प्रतिशत), खाद्य वस्तुएं (29.9 प्रतिशत) और खनिज ईंधन, स्नेहकों एवं सहबद्ध सामग्री (26 प्रतिशत) में हुई बढ़ोतरी के कारण था। वर्ष 2010–11 में निर्यातों का यूनिट मूल्य सूचकांक गिरकर -5.1 प्रतिशत पर आ गया जो मुख्यत: मशीनरी और परिवहन उपस्कर (-18.2 प्रतिशत) और पेय पदार्थ एवं तंबाकू (-11.1 प्रतिशत) में हुई गिरावट के कारण था। विभिन्न देशों के निर्यात की मात्रा के सूचकांक का अध्ययन दर्शाता है कि 2010–11 में इस सूचकांक में हुई उच्च वृद्धि चीन, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात को किए जाने वाले निर्यातों की मात्रा में उच्च वृद्धि के कारण थी।

7.16 वर्ष 2010–11 में रूपये मूल्य में आयातों में हुई बढ़ोतरी मात्रा और यूनिट मूल्य सूचकांक दोनों में हुई वृद्धि की वहज से हुई थी। मात्रा सूचकांक में 2010–11 में 10.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई जो मूलत: सामग्रियों के रूप में वर्गीकृत विनिर्मित वस्तुओं (56 प्रतिशत), पेय पदार्थ एवं तंबाकू (31.1 प्रतिशत) और रसायन एवं सहबद्ध उत्पादों (8.9) में हुई उच्च वृद्धि के कारण थी। आयातों के यूनिट मूल्य सूचकांक में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो मुख्यत: कच्चे माल, ईंधन को छोड़कर अखाद्य वस्तुओं (23 प्रतिशत), खनिज तेल, स्नेहकों एवं सहबद्ध सामग्री (17.1 प्रतिशत) तथा मशीनरी एवं परिवहन उपस्कर (10.1 प्रतिशत) के यूनिट मूल्य में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई थी।

7.17 निवल आयात-निर्यात स्थिति, जो आयातों के यूनिट मूल्य सूचकांक के अनुपात के रूप में निर्यातों के यूनिट मूल्य सूचकांक का पैमाना है, गिरकर -14.3 प्रतिशत पर आ गया। इसकी वजह इस दशक में पहली बार आयातों के यूनिट मूल्य सूचकांक में धनात्मक वृद्धि और निर्यातों के यूनिट मूल्य सूचकांक में ऋणात्मक वृद्धि का होना था। आयात-निर्यात संबंधी आय, जो आयात करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है, में 2010–11 में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो निर्यात मात्रा में जबर्दस्त वृद्धि के चलते निवल आयात-निर्यात स्थिति में अधिकतम दशकीय ऋणात्मक वृद्धि होने के बावजूद इस दशक में सर्वाधिक रही।

7.18 विश्व पण्य निर्यातों में भारत का हिस्सा जो वर्ष 2004 से तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ था, 2009 में 1.3 प्रतिशत और 2010 में 1.5 प्रतिशत हो गया। यह हिस्सा बढ़कर वर्ष 2011 के पूर्वार्ध में 1.9 प्रतिशत हो गया जो विश्व की 23.1 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि की तुलना में मुख्यत: 55 प्रतिशत के स्तर पर भारत के निर्यातों में हुई अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि के कारण संभव हुआ (सारणी 7.4)। वर्ष 2000 और 2010 के बीच विश्व निर्यातों में चीन के हिस्से में 6.5 प्रतिशतांक के स्तर पर हुई वृद्धि इस अवधि में उभरते एवं विकासशील देशों के हिस्से में हुई कुल वृद्धि का 48 प्रतिशत बैठती है, जबकि भारत के हिस्से में 0.8 प्रतिशतांक के स्तर पर हुई वृद्धि इस कुल बढ़ोतरी का केवल 6 प्रतिशत बैठती है। तथापि, वर्ष 2010 में 31.3 प्रतिशत पर और वर्ष 2011 के पूर्वार्ध में 24 प्रतिशत पर चीन की निर्यात वृद्धि दर भारत की निर्यात वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम थी। भारत के कुछ मुख्य व्यापार भागीदारों की निर्यात और आयात की अद्यतन मासिक वृद्धि दरों की सूचना बहुत उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि यूरोपीय संघ और हांगकांग की आयात एवं निर्यात-वृद्धि दरें कम हो रही है तथा चीन एवं सिंगापुर की आयात-वृद्धि दरें कम हो चुकी हैं (सारणी 7.5)।

7.19 भारत के पण्य आयात, जो वैश्विक मन्दी के कारण वर्ष 2009–10 में -5.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के चलते कम होकर 288.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गए, उनमें तेज़ी से सुधार हुआ और वे 28.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2010–11 में 369.8 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गए। ऐसा पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहकों (पीओएल) की आयात-वृद्धि में हुई 21.6 प्रतिशत तथा पीओएल-भिन्न आयातों में हुई 31.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण संभव हुआ। पीओएल आयात-वृद्धि मुख्यत: भारतीय कच्चे तेल के आयात-समूह के आयात मूल्य में हुई

सारणी 7.4 : निर्यात वृद्धि और विश्व निर्यात में हिस्सेदारी: भारत एवं अन्य चुनिन्दा देश

	मूल्य बिलियन अमरीकी डालर 2010	सीएजीआर	विकास दर % वार्षिक			विश्व निर्यात में हिस्सा (%)				हिस्से में परिवर्तन
		2000-2008	2009	2010	2011 (जनवरी-जून)	2000	2009	2010	2011 (जनवरी-जून)	2010/2000
चीन	1578	24.4	-15.9	31.3	24.0	3.9	9.7	10.5	10.1	6.5
कोरिया	466	11.9	-14.3	29.0	24.2	2.7	2.9	3.1	3.2	0.4
हांगकांग	390	7.6	-12.2	22.5	15.3	3.2	2.6	2.6	2.4	-0.6
रूस	400	20.6	-35.7	32.0	31.5	1.7	2.5	2.7	2.9	1.0
सिंगापुर	352	11.9	-20.2	30.4	21.9	2.2	2.2	2.3	2.3	0.2
मेक्सिको	298	7.3	-21.3	29.8	21.3	2.6	1.9	2.0	2.0	-0.6
ताईवान	275	7.1	-20.1	34.8	उ.न.	2.3	1.6	1.8	NA	-0.5
भारत	223	21.0	-15.2	35.1	55.0	0.7	1.3	1.5	1.9	0.8
मलेशिया	199	9.9	-24.9	26.2	17.6	1.5	1.3	1.3	1.3	-0.2
ब्राजील	202	17.3	-22.7	32.0	32.6	0.9	1.2	1.3	1.4	0.5
थाईलैंड	195	12.4	-13.6	28.6	17.3	1.1	1.2	1.3	1.3	0.2
इंडोनेशिया	158	9.9	-14.4	32.1	27.6	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0
दक्षिण अफ्रीका	82	13.9	-26.0	30.6	29.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1
ईडीई	5894	18.0	-24.4	28.4	29.2	25.4	37.1	39.1	39.8	13.6
विश्व	**15087**	**12.2**	**-22.7**	**21.9**	**23.1**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**-**

स्रोत : अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ नवम्बर, 2011 से परिकलित
टिप्पणी : ईडीई का तात्पर्य उभरते हुए और विकासशील देश है।

सारणी 7.5 : भारत के कुछ मुख्य व्यापारिक भागीदार की हालिया मासिक निर्यात एवं आयात वृद्धि दरें

	यूएसए		ईयू		चीन		हांगकांग		जापान		सिंगापुर	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2011एम1	19.0	22.0	16.5	16.9	37.6	27.3	18.7	18.7	11.9	23.8	27.1	19.3
2011एम2	16.8	16.8	19.9	20.4	2.3	24.5	24.8	24.8	19.3	20.4	21.7	12.8
2011एम3	18.8	17.4	20.1	20.2	35.8	21.0	18.4	18.4	8.1	23.9	24.4	29.3
2011एम4	20.9	16.1	20.7	21.6	29.8	3.9	6.0	6.0	-1.9	22.1	16.1	15.7
2011एम5	17.6	20.6	37.5	35.3	19.3	10.3	13.2	13.2	1.3	26.9	23.2	32.7
2011एम6	14.7	13.6	22.4	22.8	17.9	9.3	11.6	11.6	11.2	24.0	20.1	17.4
2011एम7	15.7	13.7	17.3	17.9	20.4	9.1	10.0	10.0	6.8	21.4	16.8	8.4
2011एम8	18.6	14.2	26.0	24.7	24.4	6.5	13.7	13.7	13.8	32.0	16.7	31.0
2011एम9	18.2	13.0	14.8	13.5	17.0	-3.3	2.0	2.0	12.4	23.2	14.3	14.1
2011एम10	12.1	12.2	4.2	4.5	15.8	11.2	10.7	10.7	2.6	25.7	4.0	10.8
2011एम11	11.9	12.8	6.4	3.5	13.8	1.7	8.4	8.4	1.6	18.4	9.2	18.0
2011एम12	-	-	-	-	13.4	7.4	8.1	8.1	-1.3	15.9	8.5	4.9

स्रोत : डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों से परिकलित।

बढ़ोतरी के कारण था जिसमें 2009-10 के -16.5 प्रतिशत के मुकाबले 2010-11 में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 7.4)। पीओएल आयात की मात्रा में होने वाली वृद्धि 2009-10 के 15 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 4 प्रतिशत रह गई।

7.20 तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें (भारतीय समूह) जो जुलाई 2008 में 132.47 अमरीकी डालर प्रति बैरल की ऊंचाई पर पहुंच गई थी, वैश्विक मन्दी के बाद तेज़ी से गिरकर दिसंबर 2008 में 40.61 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गईं। वर्ष 2009 से तेल की कीमतों में आवर्ती अस्थिरता के साथ-साथ बढ़ोतरी होती रही है जो अप्रैल 2011 में 118.46 अमरीकी डालर प्रति बैरल पहुंच गई और अगले महीनों में अस्थिरता की स्थिति के चलते मामूली सी कम हो गई। अभी हाल तक ब्रेन्ट तेल की कीमत लगभग 105-115 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर मंडरा रही है (चित्र 7.5)।

7.21 पीओएल-भिन्न बुलियन-भिन्न आयातों में 2010-11 में 29.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2009-10 में ऋणात्मक वृद्धि (-7.9 प्रतिशत) हुई थी। यह औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आयातों की बढ़ती मांग और निर्यातों के लिए ज़रूरी निविष्टियों के आयात की उच्चतर मांग को प्रतिबिंबित करती है।

चित्र 7.4 पी.ओ.एल. आयात

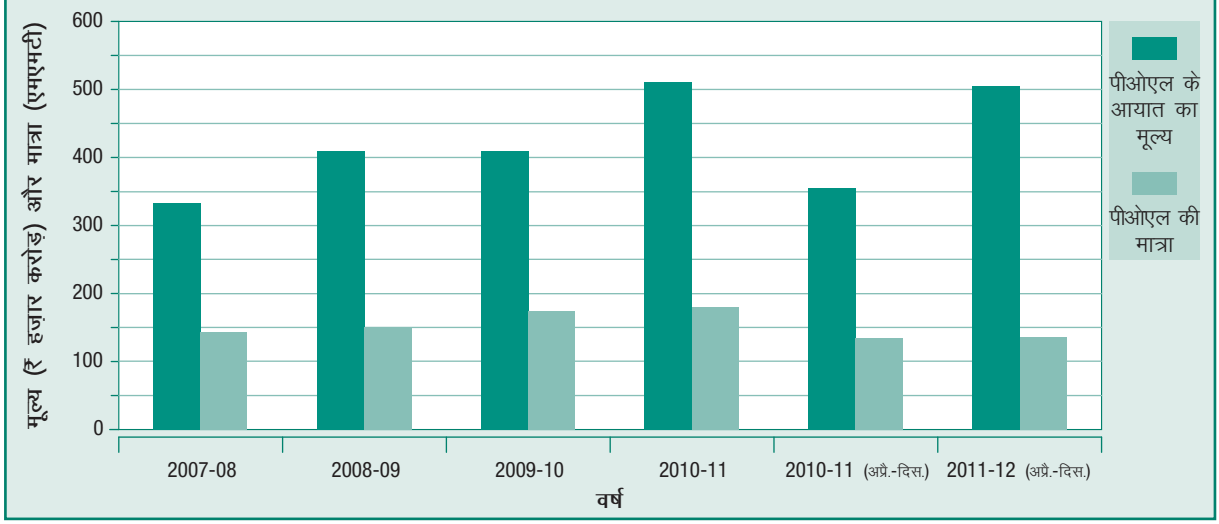

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

चित्र 7.5 कच्चे तेल की कीमत (अमरीकी डालर/बैरल)

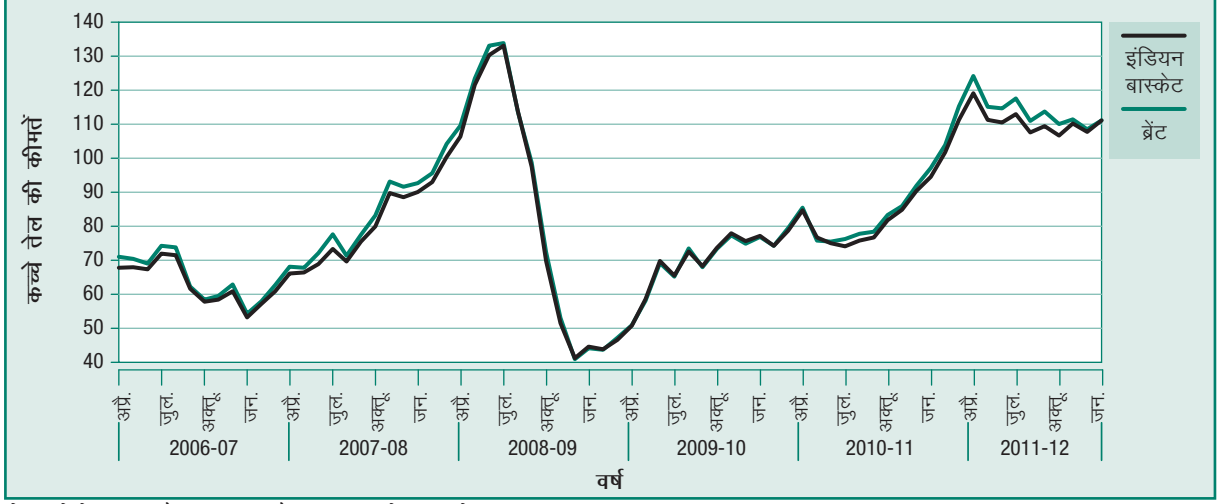

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

7.22 वर्ष 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में 391.5 बिलियन अमरीकी डालर के आयातों में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पीओएल के लिए 40.4 प्रतिशत; स्वर्ण एवं चांदी के लिए 53.8 प्रतिशत, मशीनरी के लिए 27.7 प्रतिशत; इलैक्ट्रानिक्स के लिए 24 प्रतिशत; उर्वरकों के लिए 35 प्रतिशत और कोयले के लिए 62 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 118 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पीओएल आयातों में 38.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 273.5 बिलियन अमरीकी डालर के पीओएल-भिन्न आयातों में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 50 बिलियन अमरीकी डालर के स्वर्ण एवं चांदी के आयातों में 46.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीओएल-भिन्न और बुलियन-भिन्न आयात, जो मूलत: औद्योगिक कार्यकलाप के लिए ज़रूरी पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं निर्यातों के लिए ज़रूरी आयात होते हैं, 223 बिलियन अमरीकी डालर के रहे और इनमें 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.23 व्यापार-घाटा (सीमा शुल्क आधार पर) 2009-10 के 109.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2010-11 में 118.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 8.2 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। तथापि, 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में 148.7 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा 2010-11 (अप्रैल-जनवरी) के 105.9 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे से 40.4 प्रतिशत अधिक था। कम निर्यात वृद्धि और साधारण आयात वृद्धि, जिसके कारण 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में उच्च व्यापार घाटा हुआ था, ने अनियंत्रणीय चालू खाता घाटे की संभावना की चेतावती दी है। निवल पीओएल आयात वृद्धि जो 2002-03 से धनात्मक थी और 2009-10 में -8.9 प्रतिशत पर ऋणात्मक रही, 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के चलते 2010-11 में फिर से धनात्मक हो गई। वर्ष 2011-12 के पूर्वार्ध में यह वृद्धि 34 प्रतिशत थी जो निर्यात पक्ष की तुलना में प्रधान आयात पक्ष को प्रभावित करने वाले कच्चे तेल की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों का दर्शाती है (सारणी 7.6)।

सारणी 7.6 : पीओएल व्यापार एवं गैर-पीओएल आयात में वृद्धि (अमरीकी डालर में)

	कुल आयात	पीओएल आयात	पीओएल निर्यात	निवल पीओएल आयात	गैर-पीओएल आयात	सोना एवं चांदी आयात	गैर-पीओएल गैर-सोना एवं चांदी आयात
2001-02	1.7	-10.5	12.0	-13.6	7.2	-3.1	8.9
2002-03	19.4	26.0	21.6	26.8	17.0	-6.9	20.4
2003-04	27.3	16.6	38.5	12.9	31.5	59.9	28.5
2004-05	42.7	45.1	95.9	34.4	41.8	62.6	39.0
2005-06	33.8	47.3	66.5	41.4	28.8	1.5	33.1
2006-07	24.5	30.0	60.5	19.0	22.2	29.4	21.4
2007-08	35.5	39.4	51.8	33.3	33.6	22.0	35.1
2008-09	20.7	14.7	-5.2	25.7	20.8	22.3	20.6
2009-10	-5.0	-5.0	4.6	-8.9	-3.3	35.5	-7.9
2010-11	28.2	22.0	46.5	9.8	31.4	43.5	29.3
2011-12 (अप्रैल-सितं॰)	32.7	47.7	72.7	34.0	26.8	72.8	19.1

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों से परिकलित

तथापि, 2000-01 और 2011-12 (अप्रैल-सितंबर) दोनों में कुल आयातों में पीओएल का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत पर स्थिर रहने तथा कुल निर्यातों में पीओएल निर्यातों का हिस्सा 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो जाने के चलते इस अवधि में कुल आयातों में निवल पीओएल आयातों का हिस्सा 27.2 प्रतिशत से कम होकर 18.4 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में विशेष रूप से स्वर्ण और चांदी के आयात में 53.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि ने भी व्यापार घाटे की बढ़ोतरी में योगदान दिया।

व्यापार संरचना

निर्यात संरचना

7.24 भारत के निर्यात वस्तु-समूह की क्षेत्रक संरचना में 2000 के दशक में देखे गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों में इस दशक की शुरूआत से तेज़ी आ गई है। 2000-01 से 2009-10 की 10-वर्षीय अवधि में जहां कच्चे पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों का हिस्से में 11.8 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई है, वहीं इसमें 2009-10 से 2011-12 के पूर्वार्ध तक 4.8 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। अन्य दो क्षेत्रों अर्थात् विनिर्माण एवं प्राथमिक उत्पादों के हिस्से में लगभग आनुपातिक तौर पर 2000-01 से 2009-10 के दौरान क्रमश: 11.6 और 1.1 प्रतिशतांक की कमी आई तथा 2009-10 से 2011-12 के पूर्वार्ध तक इनमें क्रमश: 1.4 एवं 2.2 प्रतिशतांक की कमी आई। विनिर्माण निर्यातों में ही बड़े अन्तर-क्षेत्रक संरचनागत परिवर्तन भी हुए हैं जिनमें सबसे अधिक घाटा उठाने वाले क्षेत्र हैं श्रम-प्रधान विनिर्माण जैसेकि वस्त्रोद्योग, चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण और हस्तशिल्प और इनका हिस्सा 2001-01 के क्रमश: 23.6, 4.4 और 2.8 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 के पूर्वार्ध में 8.7, 1.6 और 0.3 प्रतिशत रह गया। इसमें सर्वाधिक लाभ लेने वाला क्षेत्र इंजीनियरी वस्तु-क्षेत्र रहा जिसका हिस्सा 2000-01 के 15.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 के पूर्वार्ध में 22.2 प्रतिशत हो गया। एक और क्षेत्र है–इलैक्ट्रॉनिक्स जिसका हिस्सा 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 3.5 प्रतिशत हो गया तथा गिरकर 2011-12 के पूर्वार्ध में 2.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2000-01 से 2011-12 के पूर्वार्ध के दौरान रसायनों एवं सहबद्ध उत्पादों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई और ये 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गया, रत्न एवं आभूषणों में मामूली कमी हुई और ये 16.6 प्रतिशत से गिरकर 16.1 प्रतिशत पर आ गए (सारणी 7.7 और परिशिष्ट सारणी 7.3 (ख))। एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारत के अधिकतर पेट्रोलियम निर्यात परिष्कृत निर्यात हैं और विनिर्माण की श्रेणी में शामिल किए जाने के पात्र हैं। इसी प्रकार, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में अनेक मदें हैं जैसेकि सामुद्रिक निर्यात और प्रसंस्करित खाद्य-पदार्थ जो विनिर्मित मदें हैं। यदि इन्हें विनिर्माण की परिभाषा में शामिल कर लिया जाए, तो कुल निर्यातों में विनिर्माण के हिस्से में गिरावट नहीं हुई है।

7.25 कृषि और सहबद्ध उत्पादों के मामले में, अनाज, गोश्त से बने खाद्य पदार्थ, ऑयल मील तथा कॉफी में हुई निर्यात वृद्धि के कारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के पूर्वार्ध में निर्यात वृद्धि उच्च स्तर पर रही। विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों में, इंजीनियरी वस्तुओं, रत्न एवं आभूषणों तथा रसायन एवं सहबद्ध उत्पादों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वस्त्रोद्योग की निर्यात वृद्धि साधारण रही (बॉक्स 7.1)। पेट्रोलियम, कच्चे तेल और इनके उत्पादों की निर्यात वृद्धि भी बहुत अधिक रही जिसकी वजह कच्चे तेल की अधिक कीमतें और शोधन-शाला क्षमता में बढ़ोतरी होना भी रही। अयस्क और खनिज ही एकमात्र ऐसी मद है जिसकी 2011-12 के पूर्वार्ध में ऋणात्मक वृद्धि हुई और इसका कारण कर्नाटक एवं ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना था।

7.26 वर्ष 2000-01 से 2011-12 के पूर्वार्ध तक संरचना में हुआ बदलाव प्रमुख वस्तुओं के गन्तव्य-वार निर्यातों में भी देखा जा सकता है। जहां भारत से यूरोपीय संघ को किए जाने वाले पेट्रोल, कच्चे तेल और उत्पादों के निर्यात के हिस्से में वृद्धि लगभग 17 प्रतिशतांक की वृद्धि के साथ संयुक्त राज्य अमरीका के

सारणी 7.7 : प्रमुख बाजारों के अनुसार निर्यात की संरचना

	प्रतिशत हिस्सा						वृद्धि दर*				
	2000-01	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2011-12 (अप्रैल-सित.)
I. प्राथमिक उत्पाद											
विश्व	16.0	13.9	14.9	13.9	12.8	12.7	1.7	3.8	31.1	24.2	39.4
अमरीका	9.4	7.2	6.8	7.5	7.6	10.9	2.9	-13.5	44.2	42.5	101.6
ई.यू.	13.1	8.4	8.6	7.7	8.5	9.8	1.7	-5.7	16.3	15.5	51.7
चीन	45.2	64.3	65.7	43.3	62.9	44.1	-26.0	26.9	11.3	61.7	-5.9
अन्य	18.9	12.9	13.1	13.2	10.7	11.3	19.7	-1.7	43.4	11.4	51.3
(क) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद											
विश्व	14.0	9.6	10.0	9.9	8.4	9.9	9.7	1.1	38.2	18.1	64.9
अमरीका	9.0	6.0	5.8	6.6	6.5	10.1	13.1	-12.1	49.7	45.1	118.1
ईयू	11.9	6.9	7.1	6.6	7.2	7.5	6.6	-6.4	21.2	17.2	38.9
चीन	18.9	8.3	14.8	13.1	8.1	13.7	-51.9	122.9	49.2	39.5	126.6
अन्य	16.8	11.2	11.3	11.0	9.2	10.2	19.1	-3.3	39.1	14.3	59.6
(ख) अयस्क एवं खनिज											
विश्व	2.0	4.3	4.9	4.0	4.3	2.8	-12.5	9.9	16.5	37.9	-10.3
अमरीका	0.4	1.2	1.0	0.9	1.1	0.8	-29.6	-21.0	12.5	28.9	4.1
ईयू	1.3	1.4	1.5	1.1	1.4	2.3	-16.7	-2.6	-6.8	7.2	118.6
चीन	26.3	56.0	50.9	30.2	54.8	30.4	-19.6	12.8	0.3	65.6	-25.5
अन्य	2.2	1.6	1.8	2.2	1.5	1.1	24.2	9.6	69.8	-3.7	1.1
II विनिर्मित वस्तुएं											
विश्व	78.8	68.9	67.2	67.9	68.6	65.8	23.1	-5.9	42.0	25.5	34.9
अमरीका	90.6	90.2	89.1	87.6	88.2	82.1	7.1	-8.7	28.5	31.5	30.8
ईयू	86.8	79.3	73.2	72.8	73.0	74.3	20.6	-15.4	29.2	15.0	34.7
चीन	54.6	30.9	32.2	51.6	35.2	43.4	14.8	29.5	170.1	12.8	65.5
अन्य	71.4	64.5	65.1	65.4	66.8	62.6	29.6	-2.5	43.3	28.5	34.5
(क) आरएमजी सहित कपड़ा											
विश्व	23.6	10.2	10.5	8.7	9.6	8.7	4.4	-1.2	17.1	10.6	27.0
अमरीका	27.2	18.4	18.4	16.3	16.8	13.8	-4.8	-7.6	15.9	16.0	15.2
ईयू	29.2	18.2	18.5	15.4	15.9	16.3	7.9	-6.7	7.9	-3.1	35.7
चीन	9.3	1.5	1.7	2.1	2.8	3.2	31.6	44.1	102.9	120.4	48.9
अन्य	20.2	6.7	7.4	6.4	7.1	6.2	5.9	6.3	22.9	17.0	25.6
(ख) रत्न एवं आभूषण											
विश्व	16.6	15.1	16.2	14.7	14.3	16.1	42.1	3.7	27.0	9.4	58.4
अमरीका	29.3	21.7	24.2	20.7	21.2	22.3	-7.7	2.8	11.9	15.6	47.6
ईयू	11.5	8.3	6.7	6.6	6.5	8.6	24.8	-26.2	29.9	14.8	75.2
चीन	0.0	8.0	3.8	0.4	0.7	0.7	2040.3	-41.4	-81.0	-82.5	33.5
अन्य	14.4	16.8	19.2	17.8	16.5	18.2	60.5	10.7	32.2	9.6	59.1
(ग) इंजीनियरिंग वस्तुएं											
विश्व	15.7	21.6	18.2	23.8	21.7	22.2	18.7	-18.7	83.9	45.0	43.6
अमरीका	13.4	23.9	17.1	22.4	21.9	21.3	16.1	-33.9	71.1	75.6	37.0
ईयू	14.0	25.4	20.8	22.5	22.3	21.5	25.7	-25.1	40.4	22.0	27.5
चीन	9.9	9.4	12.4	37.3	17.3	21.3	-10.0	63.6	409.2	52.2	65.3
अन्य	17.5	20.8	18.2	22.8	21.9	22.6	17.9	-15.8	79.1	48.1	48.1
(घ) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद											
विश्व	10.4	12.3	12.8	11.5	12.2	11.6	7.2	0.9	26.5	24.8	34.2
अमरीका	5.7	14.8	17.2	17.1	17.3	15.1	12.8	7.4	29.9	45.0	22.5
ईयू	9.7	13.0	12.5	12.6	13.1	13.3	7.4	-11.8	30.5	28.8	34.3
चीन	15.5	4.9	5.1	4.3	5.2	6.5	-38.0	28.1	44.3	23.4	68.2
अन्य	12.4	12.1	12.9	11.2	11.6	11.0	8.6	3.2	23.7	19.4	36.0
(ड.) चमड़ा एवं चमड़े का उत्पाद											
विश्व	4.4	1.9	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	-5.5	12.1	13.9	27.3
अमरीका	3.7	1.7	1.5	1.3	1.4	1.2	16.1	-17.8	12.8	15.4	23.4
ईयू	11.4	5.9	6.3	5.2	5.9	5.9	1.0	-2.1	8.4	7.3	32.4
चीन	1.1	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	-10.2	-2.2	49.7	58.0	48.2
अन्य	1.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	-1.6	-9.9	20.4	30.4	14.4
III पेट्रोलियम, कच्चा तेल एवं उत्पाद											
विश्व	4.3	14.9	16.1	16.8	17.0	20.9	-5.2	4.6	46.5	62.6	72.7
अमरीका	0.0	0.8	2.3	3.7	2.7	5.9	-76.2	180.3	110.8	61.9	204.7
ईयू	0.0	10.6	16.9	18.4	17.4	15.2	5.7	45.4	41.8	68.0	14.9
चीन	0.0	1.1	0.8	4.5	1.0	12.8	-35.1	-8.3	805.8	80.1	1565.8
अन्य	8.1	20.0	19.9	20.0	20.8	25.7	-4.8	-3.9	43.2	61.2	77.4
कुल निर्यात											
विश्व	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	13.6	-3.5	40.5	30.0	40.6
अमरीका	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	2.0	-7.6	30.8	31.9	40.5
ईयू	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	13.9	-8.4	30.0	21.6	32.3
चीन	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-14.0	24.2	68.8	40.7	34.2
अन्य	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	19.0	-3.4	42.6	31.4	43.5

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस तथा अपनी स्वयं की गणनाएं

*वृद्धि दर अमरीकी डालर में

टिप्पणी: 1. आरएमजी का अर्थ है तैयार परिधान

2. किसी मद विशेष में हिस्से का अर्थ है उस देश को किए गए भारत के कुल निर्यातों में प्रत्येक देश का हिस्सा।

3. कुछ अवर्गीकृत मदों के कारण जोड़ संभवत: मेल न खाएं।

बाक्स 7.1 : भारत के प्रमुख विनिर्मित निर्यात

भारत के विनिर्मित निर्यातों की चार मुख्य मदें हैं इंजीनियरी वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, रसायन और संबंधित उत्पाद तथा वस्त्र (सारणी 1 देखें)। वर्ष 2007-08 से इलैक्ट्रानिक वस्तुओं ने चमड़े और विनिर्मित उत्पादों को हटाकर पांचवा स्थान ले लिया है और यहां इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का हिस्सा बढ़ रहा है और चमड़े एवं विनिर्मित उत्पादों का हिस्सा कम हो रहा है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र के निर्यातों में क्रमिक परिवर्तन हुआ है और यह वस्त्रोद्योग, चमड़ा और उसके उत्पाद, हस्तशिल्प और कालीन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों से हटकर पूंजी एवं कौशल प्रधान क्षेत्रों की ओर जा रहा है।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों के हिस्से में 1999-2000 से 2010-11 के पूर्वार्ध तक लगातार वृद्धि देखी गई है और 2010-11 और 2011-12 के पूर्वार्ध में क्रमश: 84.0 प्रतिशत और 43.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दरें रही हैं। जो मुख्यत: बहुत अधिक वृद्धि दरों वाली अवशिष्ट इंजीनियरी मदों के अलावा दो मुख्य मदों मशीनरी एवं उपकरणों की उच्च वृद्धि दरों के कारण है। 2010-11 में भारतीय इंजीनियरी निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार रहे चीन, संयुक्त राज्य अमरीका, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम। इन सभी बाजारों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई और 390 प्रतिशत पर चीन शीर्ष स्थान पर रहा।

रत्न और आभूषण, जो दूसरी प्रमुख निर्यात मद है, ने 2000-01 से लगभग 16-17 प्रतिशत का अपना हिस्सा कायम रखा है और 2011-12 के पूर्वार्ध में विनिर्माणों में 58.3 प्रतिशत पर अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की। 2010-11 में इस क्षेत्र का भारत के कुल पण्य निर्यात में लगभग 14.7 प्रतिशत बैठा है। भारत विश्व में हीरे की कटाई और पॉलिश का सबसे बड़ा केन्द्र है। हीरे के वैश्विक पॉलिश बाजार में, भारत का हिस्सा मूल्य के सन्दर्भ में 70 प्रतिशत, प्रमात्रा में 85 प्रतिशत और अदद के सन्दर्भ में 92 प्रतिशत होने का अनुमान है। रत्न एवं अभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुसार यह क्षेत्र कुल मिलाकर लगभग 34 लाख रोजगार मुहैया कराता है। रत्न एवं आभूषण विनिर्माण क्षेत्र में कई छोटी और मध्यम उद्यम इकाइयां (एसएमई) हैं जो ऐसे कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती हैं जो लगभग सभी असंगठित क्षेत्र में शामिल है।

पिछले कई वर्षों से मुख्यत: बुनियादी रसायनों, भेषजीय और प्रसाधन-सामग्री के हिस्से में कमी आने के कारण रसायनों और संबंधित उत्पादों के हिस्से में मामूली कमी देखी गई है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के पूर्वार्ध में हालांकि यह वृद्धि 26.5 प्रतिशत और 34.2 प्रतिशत अधिक रही। 2000-01 से वस्त्रोद्योग क्षेत्र के हिस्से में आई लगातार गिरावट, जो एक अंक में पहुंच गई, का मुख्य कारण तैयार परिधानों और सूती कपड़े, सूती धागे, के विनिर्मित उत्पाद के हिस्से में आई गिरावट है। जाहिर है, भारत 2005 में मल्टी फाइबर करार (एमएफए) के समापन से मिले अवसर का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है।

इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र का उत्थान, जो हालांकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, शुभ संकेत है। यह इस क्षेत्र की सहायता के लिए बनाई गई सरकार की हालिया नीतियों के कारण है जैसे कि फोकस प्रॉडक्ट स्कीम में अनेक इलैक्ट्रानिक मदों को शामिल करना तथा अनेक इलैक्ट्रानिक घटकों को सीमाशुल्क से छूट देना। जापान में आई सुनामी, जिससे जापान में आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधाग्रस्त हुई, ने भी भारत को ऐसे समय में लाभ पहुंचाया होगा जब इस क्षेत्र के लिए भारत द्वारा सहायता उपाय किए जा रहे थे।

सारणी 1: भारत के विनिर्मित निर्यातों में चार मुख्य मदों का निष्पादन

	हिस्सा				सीएजीआर	वृद्धि दर		
	1999-00	2010-11	2010-11 (अप्रैल से सित॰)	2011-12 (अप्रैल से सित॰)	1999-00 से 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-सित॰)
1. इंजीनियरी वस्तुएं	11.9	23.8	21.7	22.2	28.0	-18.7	84.0	43.6
1) मशीनरी	5.6	12.2	13.1	13.1	30.5	-13.3	55.7	40.2
क) मशीनी औजार	0.2	0.1	0.1	0.1	20.6	-26.4	12.8	18.3
ख) मशीनरी एवं उपकरण	3.2	4.8	4.9	4.6	28.1	-13.3	25.2	31.6
ग) परिवहन उपस्कर	2.2	7.3	8.1	8.4	33.9	-12.9	86.6	45.7
2) लोहा एवं इस्पात	2.3	2.6	2.3	2.2	24.5	-39.2	80.0	31.5
क) लोहा एवं इस्पात छड़ आदि	0.3	0.4	0.4	0.5	30.4	-34.2	49.4	50.2
ख) प्राथमिक एवं परिष्कृत लोहा एवं इस्पात	2.0	2.2	1.9	1.7	23.5	-40.4	87.8	27.1
3) अन्य इंजीनियरी वस्तुएं	4.1	9.1	6.2	7.0	25.9	-21.7	145.7	56.8
क) लौह मिश्रित धातु	0.2	1.2	1.0	0.6	43.6	-43.1	234.6	-14.2
ख) उत्पादों के अलावा एल्युमिनियम	0.4	0.4	0.3	0.2	14.5	11.3	79.2	0.3
ग) अलौह धातुएं	0.1	3.7	1.2	1.1	60.5	5.4	323.2	29.5
घ) धातु विनिर्माण	3.3	3.8	3.7	2.9	22.5	-27.2	70.5	10.6
ङ) अवशिष्ट इंजीनियरी वस्तुएं	0.1	0.1	0.1	2.1	21.3	-5.9	47.4	3512.9
2. रत्न एवं आभूषण	20.4	14.7	14.3	16.1	15.9	3.7	27.0	58.4
3. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	13.4	11.5	12.2	11.6	19.3	0.9	26.5	34.2
1 बुनियादी रसायन, भेषज एवं प्रसाधन सामग्री	8.4	7.7	8.2	7.5	19.8	0.7	22.0	29.2
2 प्लास्टिक एवं लिनोलियम	1.6	1.8	2.0	2.2	19.7	10.4	37.7	56.1
3 रबड़, शीशा एवं अन्य उत्पाद	2.4	2.2	2.4	2.6	18.7	-0.5	33.2	51.4
4 अवशिष्ट रसायन संबद्ध उत्पाद	0.9	0.6	0.5	0.5	14.6	-5.2	43.7	29.9
4. वस्त्रोद्योग	25.0	8.7	9.6	8.7	8.6	-1.2	17.1	27.0
1 तैयार परिधान	13.0	4.5	4.8	4.5	9.7	-2.0	4.6	29.4
2 कपास, धागा, कपड़े, तैयार कपड़े	8.4	2.2	2.5	2.2	3.4	-11.1	48.8	22.6
3 मानव निर्मित वस्त्र एवं तैयार कपड़े	2.3	1.8	2.0	1.9	16.2	19.7	16.9	35.0
4 प्राकृतिक रेशम के वस्त्र	0.6	0.1	0.1	0.1	4.9	-18.4	21.2	-34.4
5 ऊन एवं ऊनी विनिर्माण	0.1	0.0	0.0	0.1	8.0	-10.3	16.6	59.9
6 नारियल जटा एवं नारियल जटा विनिर्माता	0.1	0.1	0.1	0.1	13.9	7.7	-4.9	31.3
7 पटसन विनिर्माता	0.3	0.2	0.2	0.2	10.3	-28.4	110.2	-4.2

स्रोत डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों से परिकलित।

मुकाबले अधिक रही, वहीं भारत के यूरोपीय संघ को किए जाने वाले विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के हिस्से में आई गिरावट भी लगभग 13.7 प्रतिशतांक पर अधिक है। तथापि, भारत से चीन को पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों के निर्यात के हिस्से में नाटकीय वृद्धि हुई है। भारत से चीन को अयस्कों एवं खनिजों के निर्यात के हिस्से में 2008-09 से गिरावट आनी शुरू हो गई है और यह 2011-12 के पूर्वार्ध में 30 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसके परिणाम-स्वरूप विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में वृद्धि हुई है। विनिर्माताओं में, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका एवं अन्य देशों को वस्त्रों के हिस्से में 2000-01 से गिरावट 10 प्रतिशतांक से ऊपर कमोबेश समान रही। तथापि, भारत से चीन को वस्त्रों के निर्यात के हिस्से में वृद्धि हुई है, भले ही वह कम हो। इन चारों बाजारों को भारत की इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के हिस्से में वृद्धि हुई है। हालांकि 2010-11 में इस मद का भारत से चीन को किए निर्यात हिस्से में बड़ा उछाल आया और फिर थोड़ी कमी हुई, अन्य तीन बाजारों में 2011-12 के पूर्वार्ध में हिस्सा 21-22 प्रतिशत के दायरे में बना हुआ है। जहां संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ बाजारों को रत्न एवं आभूषणों के निर्यात के हिस्से में कमी हुई है, वहीं ''अन्य'' के मामले में वृद्धि हुई है। इस मद के सन्दर्भ में चीन का हिस्सा नगण्य है। भारत के निर्यातों में रसायन और संबंधित उत्पादों के हिस्से में संयुक्त राज्य अमरीका बाजार को लगभग 10 प्रतिशतांक और यूरोपीय संघ बाजार को लगभग 3.5 प्रतिशतांक की बढ़त दर्ज की गई (सारणी 7.7)।

निर्यात विविधता

7.27 वर्ष 2009 के समान ही, भारत का दो अंकीय सुमेलित प्रणाली (एचएस) स्तर पर कुल 99 वस्तुओं में से 48 वस्तुओं में 1 प्रतिशत या अधिक का वैश्विक निर्यात-हिस्सा था। तथापि, वर्ष 2009 में 12 मदों में इसका 5 प्रतिशत या अधिक का हिस्सा कम होकर 10 मदों तक सीमित रह गया है और बर्ड स्किन, चमड़े, बनावटी फूल, मानव केश, और अयस्क, स्लैग और राख सूची से निकाल ली गई हैं। (सारणी 7.8)। मोती, बहुमूल्य पत्थर, धातुएं, सिक्के आदि को छोड़कर, सभी नौ मदों में 2009 के मुकाबले 2010 में, ग्लोबल हिस्से में बढ़ोतरी देखी गई जहां कपास सूची में सबसे ऊपर रहा। लेकिन मोती, बहुमूल्य पत्थर, धातुओं, सिक्कों आदि के अलावा इन अधिकतर 10 मदों का वैश्विक निर्यात में बहुत छोटा हिस्सा था।

7.28 हालांकि भारत ने अपने निर्यात बाजारों के विविधीकरण में बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी निर्यात वस्तु समूह की विविधता के लिए ही नहीं बल्कि विश्व व्यापार की प्रमुख मदों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखने के लिए भी अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है (बॉक्स 7.2)।

आयात संरचना

7.29 आयातों के मामले में कोई भी भारी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं सिवाय स्वर्ण और चांदी के आयातों के हिस्से में हुई अचानक वृद्धि के जो 2000-01 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर

सारणी 7.8 : विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा: जिन्सवार (5 प्रतिशत से अधिक हिस्सा)

क्र. सं.	उत्पाद कोड	उत्पादन लेबल	2006	2007	2008	2009	2010	हिस्से में परिवर्तन 2010/2009
1	'52	कपास	6.84	8.47	8.60	7.61	11.86	4.25
2	'13	लाख, गम, रेजिन, वनस्पति सार एवं सत्त	10.55	9.48	9.67	7.57	11.56	3.99
3	'50	रेशम	11.39	10.53	10.17	9.73	10.30	0.57
4	'57	कार्पेट एवं अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग	9.56	8.73	8.40	8.37	9.51	1.14
5	'53	वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर, पेपर यार्न, बुने हुए फेब्रिक	4.21	4.59	6.09	6.28	9.50	3.21
6	'71	मोती, बहुमूल्य पत्थर, धातु, सिक्के आदि	6.49	6.60	5.70	10.20	7.80	-2.39
7	'14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री, वनस्पति उत्पाद	4.46	4.83	5.45	5.09	7.25	2.17
8	'63	अन्य निर्मित टेक्सटाइल वस्तुएं, सेट, बुने हुए कपड़े आदि	6.37	5.73	5.39	5.46	6.01	0.55
9	'09	कॉफी, चाय, मेट एवं मसाले	5.01	5.18	5.31	4.98	5.41	0.43
10	'54	मानवनिर्मित फिलामेंट	2.55	2.88	3.71	5.25	5.33	0.07

स्रोत: यूएन-आईटीसी व्यापार मानचित्र डाटा, 2010 पर आधारित राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) डाटा से संगणित।

बॉक्स 7.2 : भारत के निर्यात वस्तु-समूह के विविधीकरण की आवश्यकता

नवीनतम यूएन कामट्रेड आंकड़ों का उपयोग करते हुए चार अंकीय सुमेलित प्रणाली (एचएस) स्तर पर विश्व की शीर्ष आयात मदों में भारत के निर्यात की स्थिति का आन्तरिक अध्ययन निम्नलिखित परिणाम दर्शाता है:

- वर्ष 2010 में विश्व के 100 शीर्ष आयातों में भारत के पास 5 प्रतिशत और इससे अधिक के हिस्से वाली केवल छ: मदें हैं।
- वर्ष 2010 में विश्व के शीर्ष 100 आयातों में, भारत के पास 2 प्रतिशत और इससे अधिक के हिस्से वाली केवल 15 मदें हैं। इनमें से केवल 3 मदें शीर्ष 25 में और 4 मदें शीर्ष 30 में हैं। इन 15 मदों में, 9 मदें ऐसी हैं जिनमें वर्ष 2010 में विश्व की आयात वृद्धि की तुलना में भारत की निर्यात वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसी तीन मदें हैं नामश: रोस्टिड आयरन पाइराइट सहित लौह अयस्क और सांद्रण (कोड 2601); हीरे जिन पर काम हुआ हो या नहीं लेकिन जो जड़े या सेट न किए गए हों (कोड 7102) और चपटे रोल किए गए लौह उत्पाद (कोड 7210) जिनमें विश्व की आयात वृद्धि भारत की निर्यात वृद्धि के मुकाबले अधिक है और भारत की कोई ऋणात्मक वृद्धि नहीं है। इनमें से तीसरी मद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो कि एक विनिर्मित मद है और जिसकी वैश्विक निर्यात वृद्धि भारत की निर्यात वृद्धि के दोगुने से भी ज्यादा है। तीन अन्य मदें ऐसी भी हैं जिनमें भारत की निर्यात वृद्धि ऋणात्मक है और वैश्विक आयात वृद्धि धनात्मक। लेकिन यह मुख्यत: आधार प्रभाव के कारण है (सारणी 1 देखें)

सारणी 1 : चार अंकीय स्तर पर विश्व के शीर्ष 100 आयातों में भारत के 2 प्रतिशत और इससे अधिक के हिस्से वाली निर्यात मदें

रैंक	एचएस4	मद	विश्व में भारत का हिस्सा 2010	2010 में वृद्धि दर	
				भारत निर्यात	विश्व आयात
1	2710	पेट्रोलियम तेल और तेल	5.8	57.8	33.1
12	2601	लौह अयस्क और सांद्रण इत्यादि	4.2	16.0	72.8
15	7102	हीरे, कटाई किए गए अथवा नहीं	18.0	33.4	47.9
29	8803	शीर्ष सं. 88.01 या 88.02 की वस्तुओं के पुर्जे	2.1	57.5	7.0
31	7403	परिष्कृत तांबा और तांबा मिश्र धातु अपरिष्कृत	6.6	341.6	44.2
40	6204*	महिलाओं अथवा लड़कियों के सूट, ऑनसाम्बल, जैकिट, ब्लेज़र आदि	3.2	-4.6	3.4
44	6403	रबड़, प्लास्टिक, चमड़े के बाहरी सोल वाले जूते-चप्पल	2.4	13.7	11.0
53	7210	लोहे अथवा गैर मिश्रित धातु स्टील इत्यादि की लोहे की चादर	3.0	15.9	35.9
62	7113*	आभूषण और इनके भाग इत्यादि	18.2	-26.1	30.1
64	2902	चक्रीय हाइड्रोकार्बन	3.4	40.2	35.8
67	6109*	टी शर्ट, कमीज़ एवं अन्य बण्डी बुनी हुई अथवा क्रोशिए से बुनी हुई	4.3	-12.7	9.6
70	7202	लौह मिश्रित धातु	5.8	170.7	58.3
72	3902	प्रोपिलीन अथवा अन्य ओलिफिम आदि के पोलिमर्स	2.3	115.5	34.2
88	8419	मशीनरी, संयंत्र अथवा प्रयोगशाला के उपस्कर आदि	2.4	35.1	-0.9
97	2304	तेल, खली और अन्य ठोस अवशेष आदि	5.6	21.9	1.1

स्रोत : 8 फरवरी 2012 को तैयार यूएन कामट्रेड आंकड़ों से संगणित

टिप्पणी *आरंभिक वर्षों में विश्व आयात वृद्धि ऋणात्मक थी और आरंभिक वर्षों में भारत की निर्यात-वृद्धि धनात्मक थी जबकि 2010 में विपरीत स्थिति थी।

***रैंक शीर्ष 100 विश्व आयातों में है।**

- शीर्ष 100 मदों में, कई मदें ऐसी हैं जिनमें भारत ने पहले ही सक्षमता हासिल कर ली है लेकिन इनमें भारत का हिस्सा बहुत छोटा है। इनमें से कुछ साधारण मदें हैं नल, टोंटी, वाल्व और पाईपों, बॉयलर शेल, टैंक, टंकी के ऐसे ही पुर्जे इत्यादि जिनमें दबाव कम करने वाले वाल्व और तापस्थायी नियंत्रित वाल्व (8481); रबड़ के नए वायवीय टायर (4011); लोहे अथवा गैर मिश्रित इस्पात की 60 एमएम या उससे अधिक की मोटाई वाली हॉट रोल्ड, क्लैडन की गई, प्लेटिड अथवा कोटिड (कोड 7208) चादरें; ट्रंक, सूटकेस, वेनिटी केस, एक्जीक्यूटिव केस, ब्रीफकेस, स्कूली बस्ते, चश्मे के केस, दूरबीन के केस, कैमरे के केस, संगीत वाद्ययंत्र, बन्दूक के बक्से/पेटी खोल और इसी तरह के डिब्बे (4202); अन्य खिलौने; छोटे आकार के (पैमाने) मॉडल और इसी तरह के मनोरंजक वस्तुएं, चलती हो अथवा नहीं; सभी तरह की पहेलियां (9503); स्टेनलेस स्टील के सभी उत्पाद जिनकी 600 एमएम या उससे अधिक की मोटाई हो (7219); विद्युतीय मोटर और जेनरेटर (जेनरेटिंग सेट को छोड़कर) (8501); पेच बोल्ट, नट-स्क्रू, स्क्रू हुक, रिवेट, कॉटर, कोटर-पिन, वाश स्प्रिंग वाशर सहित) और लोहे अथवा इस्पात की इसी तरह की वस्तुएं (7318) और कपड़े की कई तरह की मदें।
- इस तरह, शीर्ष मदों की वैश्विक मांग में सुस्पष्ट हिस्से को देखते हुए भारत द्वारा अपने निर्यात-वस्तु समूह का अधिक विविधीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत : आंतरिक अध्ययन, आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग

2011-12 के पूर्वार्ध में 13.3 प्रतिशत हो गयी और मोती, मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान नगीनों के आयात के हिस्से में हुई गिरावट के जो 2000-01 में 9.6 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 के पूर्वार्ध में 6.0 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत वस्तुओं के आयातों का हिस्सा जो 2000-01 में 10.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 15.5 प्रतिशत हो गया था, फिर गिरना शुरू हुआ और 2011-12 के पूर्वार्ध में 11.6 प्रतिशत पर आ गया। पीओएल आयातों का हिस्सा जो 2000-01 में 31.3 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 28.6 प्रतिशत पर आ गया था, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बढ़कर 2011-12 के पूर्वार्ध में 31.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया (सारणी 7.9)।

व्यापार की दिशा

7.30 निर्यात और आयात बाजारों की विविधता के संदर्भ में भारत ने सफलता की गाथा रची है। कुल व्यापार में एशिया और आसियान का हिस्सा 2000-01 के 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 के पूर्वार्ध में 57.3 प्रतिशत हो गया जबकि यूरोप और अमरीका का हिस्सा 42.5 प्रतिशत से गिरकर 30.8 प्रतिशत रह गया। इससे भारत को यूरोप और अमरीका से उपजे वैश्विक संकट का सामना करने में मदद मिली है। असल में, आज शीर्षस्थ 15 व्यापार भागीदारों में से केवल पांच विकसित पश्चिमी देश हैं जबकि 2000-01 में सात देश थे। हालांकि शीर्षस्थ 15 देशों के पास अब भी 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल-सितम्बर) (सारणी 7.10) में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, फिर भी इन वर्षों में शीर्षस्थ देश ही बदल गए हैं। मुख्य परिवर्तन यह है कि नई सूची में इटली, मलेशिया, फ्रांस और आस्ट्रेलिया के स्थान पर इंडोनेशिया, कोरिया, ईरान और नाइजीरिया का प्रवेश हुआ है। यदि हम 2000-01 के शीर्षस्थ 15 देशों का हिस्सा देखें तो आज यह 59.6 प्रतिशत है जबकि 2000-01 में आज के शीर्षस्थ देशों का हिस्सा 55.5 प्रतिशत था। भारत के व्यापार की दिशा में एक दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि अमरीका जो 2007-08 में पहले स्थान पर था, बाद के वर्षों में पदावनत होकर तीसरे स्थान पर आ गया है और संयुक्त राज्य अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है जिसके बाद चीन का स्थान आता है। यह स्थिति 2008-09 से 2010-11 तक बनी रही है।

7.31 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2009 में 5.71 प्रतिशत के स्तर पर सबसे बड़े घाटों में से एक है। प्रमुख देशों में केवल दो ही व्यापार देशों-हांगकांग और यूनाइटेड किंगडम का अनुपात भारत के अनुपात से अधिक है।

सारणी 7.9 : भारत के आयातों की जिन्सवार संरचना

जिन्स समूह	प्रतिशत हिस्सा					सीएजीआर	वृद्धि दर (प्रतिशत)[क]			
	2000-01	2009-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2000-to 2008-2009	2009-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2011-12 (अप्रैल-सित.)
I. खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद जिनमें से	**3.3**	**3.7**	**2.9**	**3.1**	**3.1**	**18.0**	**69.0**	**0.8**	**19.7**	**35.0**
1. अनाज	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	123.0	14.3	253.1	-54.5
2. दलहन	0.2	0.7	0.4	0.5	0.3	36.0	58.8	-24.1	6.3	-2.6
3. खाद्य तेल	2.6	1.9	1.8	1.8	2.1	12.6	62.3	17.4	25.0	56.1
II. ईंधन जिसमें से	**33.5**	**33.2**	**31.3**	**31.6**	**35.1**	**24.9**	**-5.5**	**20.8**	**33.7**	**47.6**
4. पीओएल	31.3	30.1	28.6	28.2	31.4	24.4	-5.0	22.0	33.0	47.7
III. उर्वरक	**1.3**	**2.3**	**1.9**	**2.5**	**1.7**	**44.6**	**-48.3**	**3.4**	**30.4**	**-11.8**
IV. पूंजीगत वस्तुएं, जिनमें से	**10.5**	**15.0**	**13.1**	**12.8**	**11.6**	**31.2**	**-8.2**	**12.4**	**10.8**	**20.9**
5. इलेक्ट्रिकल एवं मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	5.9	7.4	6.4	6.5	6.3	29.6	-10.2	11.7	12.0	30.2
6. इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	28.6	-15.1	23.4	19.3	29.5
7. परिवहन संबंधी उपकरण	1.4	4.1	3.1	2.8	1.8	44.0	-11.6	-2.2	-10.3	-12.8
V. अन्य, जिनमें से	**46.3**	**42.6**	**47.7**	**46.8**	**45.7**	**22.7**	**1.3**	**43.5**	**51.6**	**29.6**
8. रसायन	5.9	5.2	5.2	5.5	5.1	22.2	0.0	27.9	34.0	23.8
9. मोती, कीमती पत्थर अर्द्ध कीमती पत्थर	9.6	5.6	9.4	8.5	6.0	16.4	-2.4	114.0	173.4	-5.8
10. सोना और चांदी	9.3	10.3	11.5	10.3	13.3	21.1	35.5	43.5	55.5	72.8
11. इलेक्ट्रिक वस्तुएं	7.0	7.3	7.2	7.6	7.2	26.4	-10.0	26.7	25.4	26.2
कुल आयात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**25.0**	**-5.0**	**28.2**	**37.6**	**32.7**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

द्विपक्षीय व्यापार शेष को प्रतिबिम्बित करने वाले निर्यात-आयात के अनुपात (सारणी 7.10) यह दर्शाते हैं कि 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में भारत का पांच देशों नामशः संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष था। गौरतलब दिलचस्प बात यह है कि भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार अधिशेष है, जहां से यह भारी मात्रा में तेल आयात करता है, जबकि सऊदी अरब, ईरान और नाईजीरिया जैसे तेल निर्यातकों के साथ इसका उच्च व्यापार घाटा है। तथापि, 2011-12 के पूर्वार्ध (अप्रैल-सितम्बर) में तेल की बढ़ती कीमतों के कारण संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का व्यापार अधिशेष घाटे की स्थिति में चला गया है हालांकि यह काफी कम है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है–भारत का चीन और स्विट्जरलैंड के साथ बढ़ता व्यापार घाटा जो 2009-10 के क्रमशः 19.2 बिलियन अमरीकी डालर और 14.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2010-11 में 23.9 बिलियन अमरीकी डालर और 24.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया तथा आगे और बढ़कर 2011-12 के पूर्वार्ध में 20 बिलियन अमरीकी डालर और 14.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसका कारण है चीन से मशीनरी और स्विट्जरलैंड से सोने का बढ़ता आयात। यह विश्लेषण द्विपक्षीय व्यापार शेष के संबंध में एक अधिक केंद्रित कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।

7.32 क्षेत्र-वार, निर्यातों में भारत की विविधता इस तथ्य का प्रमाण है कि एशिया और आसियान का हिस्सा 2000-01 के 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 56.2 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका का हिस्सा 46.9 प्रतिशत से गिरकर 30.8 प्रतिशत रह गया। संयुक्त अरब अमीरात ने 2008-09 में संयुक्त राज्य अमरीका को भारत के निर्यातों के अग्रणी गंतव्य से पदच्युत कर दिया है और 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के पूर्वार्ध में क्रमशः 13.4 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत निर्यात हिस्से के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। सभी शीर्ष तीन गंतव्यों अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन को किए जाने वाले भारत के निर्यातों ने 2010-11 में क्रमशः 43.3 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत और 69.1 प्रतिशत और 2011-12 के पूर्वार्ध में क्रमशः 21.9 प्रतिशत, 40.7 प्रतिशत और 34.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

7.33 एशिया और आसियान भारत के आयातों का प्रमुख स्रोत बने रहे हैं। 2000-01 की तुलना में 2011-12 के पूर्वार्ध में आयातों

सारणी 7.10 : प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ भारत का व्यापार-हिस्सा तथा आयात-निर्यात अनुपात

क्र. सं.	देश	कुल व्यापार में हिस्सा					आयात-निर्यात अनुपात [क]				
		2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2011-12 (अप्रैल-सित.)
1	यू॰ए॰ई॰	9.76	9.29	10.81	10.87	9.25	1.04	1.23	1.05	0.88	0.99
2	चीन	8.59	9.09	10.16	9.72	9.27	0.29	0.37	0.45	0.26	0.28
3	अमरीका	8.18	7.83	7.35	7.85	7.23	1.14	1.15	1.27	1.16	1.52
4	सऊदी अरब	5.09	4.49	4.13	4.27	4.44	0.26	0.23	0.26	0.23	0.22
5	स्विटजरलैंड	2.54	3.26	4.10	3.55	4.28	0.07	0.04	0.03	0.03	0.05
6	हांगकांग	2.71	2.70	3.18	3.11	3.15	1.02	1.67	1.10	1.24	1.26
7	जर्मनी	3.80	3.37	3.00	2.97	3.04	0.53	0.52	0.57	0.49	0.52
8	सिंगापुर	3.26	3.01	2.81	3.02	3.62	1.09	1.17	1.44	1.19	1.92
9	इण्डोनेशिया	1.91	2.52	2.60	2.40	2.79	0.38	0.36	0.63	0.50	0.47
10	बेल्जियम	2.09	2.09	2.40	2.26	2.09	0.78	0.62	0.73	0.62	0.87
11	कोरिया	2.62	2.57	2.35	2.33	2.14	0.46	0.40	0.39	0.30	0.37
12	जापान	2.24	2.22	2.23	2.39	2.15	0.39	0.54	0.60	0.60	0.48
13	ईरान	3.04	2.87	2.20	2.14	1.68	0.21	0.16	0.25	0.21	0.24
14	नाईजीरियाा	2.12	1.86	2.10	2.06	2.39	0.18	0.19	0.21	0.18	0.14
15	यूके	2.58	2.29	2.02	2.02	2.06	1.13	1.40	1.33	1.36	1.13
	कुल शीर्षस्थ 15 देश	60.54	59.45	61.45	60.97	59.55	0.57	0.60	0.63	0.55	0.59
कुल व्यापार		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.61**	**0.62**	**0.68**	**0.60**	**0.63**

स्रोतः डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

टिप्पणी : [क]0 से 1 के बीच आयात एवं निर्यात के सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का आयात निर्यात से अधिक है तथा एक से अधिक सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का निर्यात आयात से अधिक है।

की संरचना यह दर्शाती है कि एशिया और आसियान के हिस्से में बढ़ातरी हुई है और यह 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 61.5 प्रतिशत हो गया है तथा यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका का हिस्सा घट गया है और क्रमश: 27.5 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत से घटकर 18.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत रह गया है। 2011-12 (अप्रैल-सितम्बर) में देश-वार, चीन भारत के कुल आयातों में 11.7 प्रतिशत के हिस्से के चलते सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (7.6 प्रतिशत), स्विट्जरलैंड (6.6 प्रतिशत), सऊदी अरब (6 प्रतिशत) और संयुक्त राज्य अमरीका (4.7 प्रतिशत) का स्थान आता है। शीर्ष 15 व्यापार भागीदारों में, कच्चे तेल, सोना और चांदी तथा कच्चे तेल के साथ-साथ खाद्य तेलों के आयातों के कारण नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया से किए गए भारत के आयात ने 2011-12 (अप्रैल-सितम्बर) में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की। हालांकि ईरान, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात और बेल्जियम से किए गए भारत के आयातों में कम वृद्धि दर्ज की गई।

सेवाओं का विश्व व्यापार

7.34 3.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर की वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व निर्यात के हिस्से में विकसित पश्चिमी देशों का दबदबा है सिवाय चीन, भारत और सिंगापुर के जो सेवाओं के शीर्ष व्यापारियों की सूची में भी दर्ज हैं। संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, चीन और जापान वाणिज्यिक सेवाओं में जहां विश्व व्यापार के एक तिहाई हिस्से पर काबिज हैं, वहीं वाणिज्यिक सेवाओं में सिर्फ यूरोप का ही कुल व्यापार में 45 प्रतिशत हिस्सा है। विकसित पश्चिमी देश प्रमुख व्यापारी हैं जबकि वृद्धि के संदर्भ में एशियाई देशों द्वारा 2008 से वाणिज्यिक सेवाओं के अपने निर्यातों में प्रतिवर्ष औसतन 13 प्रतिशत की वृद्धि करने के चलते ये अगुआ बने हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी, 2011 के अनुसार विश्व पण्य निर्यातों ने जहां 2010 में मजबूती से छलांग मारी और मात्रा के संदर्भ में इनमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व निर्यातों में 2010 में मात्र 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 3,695 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि विश्व पण्य और सेवा निर्यात दोनों ही संकट-पूर्व (2008) स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। यह पुनरुत्थान विभिन्न क्षेत्रों में भी एक-समान नहीं हुआ है। वाणिज्यिक सेवाओं की सबसे अधिक तीव्र वृद्धि एशिया में रही है, जहां भारत और चीन की अगुआई में 2010 में निर्यात में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय संघ के निर्यातों में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मध्य और दक्षिण अमरीका तथा कैरिबियन देशों के साथ-साथ स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से होने वाले वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यातों में 12 प्रतिशत; उत्तर अमरीका में 9 प्रतिशत और अफ्रीका में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आंतर-यूरोपीय संघ व्यापार को छोड़कर यूरोपीय संघ (27) को समग्र मानकर वाणिज्यिक सेवाओं के शीर्ष पांच निर्यातक और आयातक देश हैं यूरोपीय संघ (27), अमरीका, चीन, जापान और भारत तथा वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात और आयात दोनों में उसी स्थान पर हैं। शीर्ष पांच में केवल चीन और जापान ही वाणिज्यिक सेवाओं के निवल आयातक हैं।

7.35 चीन और भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाणिज्यिक सेवा व्यापार में अब बढ़ती भूमिका निभा रही हैं। 2010 में, चीन का वाणिज्यिक सेवा व्यापार निर्यातों में हुई 32 प्रतिशत की वृद्धि के चलते 2005 के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर कुल 362 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है जो वैश्विक हिस्से का 6.6 प्रतिशत है। भारत वाणिज्यिक सेवा व्यापार में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है जब इसका हिस्सा पांच वर्ष पहले के 2.8 प्रतिशत के मुकाबले 4.3 प्रतिशत हो गया। 2010 में इसके निर्यात में 33 प्रतिशत और आयात में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे यह वाणिज्यिक सेवाओं का अत्यंत सक्रिय निर्यातक बन गया है। केवल मकाऊ और चीन जिनका निर्यातों में 19वां स्थान है, ने 52 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की है, हालांकि ये भी शीर्ष 40 निर्यातकों में शामिल नहीं हैं। आंतर-यूरोपीय संघ व्यापार को बाहर नहीं किए जाने पर भी और यूरोपीय संघ के देशों को पृथक-पृथक माने जाने पर भी, भारत वाणिज्यिक सेवाओं के आयात और निर्यात दोनों में 7वें स्थान पर शीर्ष दस में है।

7.36 वाणिज्यिक सेवाओं की सभी तीन श्रेणियां नामश: परिवहन, यात्रा और अन्य वाणिज्यिक सेवाएं 2010 में हुई अच्छी खासी वृद्धि के चलते फिर से सकारात्मक दायरे में आ गईं। इनमें से परिवहन क्षेत्र में, आंशिक रूप से 2009 में उच्च ऋणात्मक वृद्धि के कारण 2000-05 की औसत वार्षिक वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई (सारणी 7.11)।

7.37 विश्व यात्रा निर्यात में, वर्ष 2010 में वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व निर्यात के एक चौथाई हिस्से के साथ यूरोप का हिस्सा 41.1 प्रतिशत है जो 2005 से लगभग 8 प्रतिशतांक बिन्दु की गिरावट दर्शाता है। परिवहन सेवाओं के निर्यात में, वाणिज्यिक

सारणी 7.11 : प्रमुख श्रेणियों के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं का विश्व निर्यात, 2009

	मूल्य (बिलियन अमरीकी डालर में)	वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन			
	2010	2000-05	2005-2010	2009	2010
वाणिज्यिक सेवाएं	3695	11	8	-12	9
परिवहन	785	11	7	-23	15
यात्रा	940	8	6	-9	8
अन्य वाणिज्यिक सेवाएं	1970	13	10	-8	7

स्रोत : डब्ल्यू टी ओ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी, 2011 से संकलित।

सेवाओं के वैश्विक निर्यात में 21.3 प्रतिशत हिस्से के साथ यूरोपीय देशों, एशिया और उत्तर अमरीका का हिस्सा क्रमश: 47.6 प्रतिशत, 28.8 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत था। अन्य वाणिज्यिक सेवाएं वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यातों का प्रमुख घटक हैं जिनका हिस्सा 53.3 प्रतिशत है और इन निर्यातों से आधे निर्यात यूरोप से, मुख्यत: यूरोपीय संघ से किए जाते हैं। ''अन्य वाणिज्यिक सेवाओं'' के निर्यात में एशिया का हिस्सा 25.4 प्रतिशत और उत्तरी अमरीका का हिस्सा 18.2 प्रतिशत था। जहां सेवाओं के व्यापार में वापस उछाल आया, वहीं ''अन्य वाणिज्यिक सेवाओं'' के सभी क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में समुत्थान एक समान नहीं रहा। यहां तक कि अधिकांश सेवाओं के मामले में संकट-पूर्व स्तर भी हासिल नहीं हो पाया। परिवहन सेवाओं के निर्यात में समुत्थान मुख्यत: एशिया के निर्यातों से प्रेरित था जहां प्रमुख निर्यातक देशों ने दो-अंकीय वृद्धि दर हासिल की। चीन में, निर्यातों में 45 प्रतिशत तथा कोरिया गणराज्य में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग और जापान से निर्यात का क्रमश: 28 प्रतिशत और 23 प्रतिशत तक विस्तार हुआ। यूरोप में धीमी रफ्तार में सुधार हुआ जहां यूरोपीय संघ की 8 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि और नार्वे की निर्यात वृद्धि 2 प्रतिशत रही।

7.38 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, वर्ष 2010 में वैश्विक रूप से अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 6.6 प्रतिशत की तेजी आने से मंदी से छाई गिरावट काफी हद तक प्रतिसंतुलित हो गई। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में यात्रा निर्यातों में तेजी आई। फलते-फूलते गेमिंग क्षेत्र की मेहरबानी से वर्ष 2010 में मकाओ, चीन विश्व के पांचवें सबसे बड़े यात्रा-निर्यातक देश बन गए जब उनकी यात्रा प्राप्तियों में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और विश्व यात्रा निर्यात में इनका हिस्सा 2.9 प्रतिशत पर पहुंचकर 5 वर्ष में दोगुने से भी अधिक हो गया। अन्य एशियाई देशों में भी यात्रा निर्यात तेजी से बढ़ा, जहां पर्यटन क्षेत्र ने बहुत तेजी से विकास किया। चीन के यात्रा निर्यात में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि हांगकांग, यह वृद्धि 35 प्रतिशत तक थी। थाईलैण्ड के यात्रा निर्यात में 26 प्रतिशत और मलेशिया के यात्रा-निर्यात में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमरीका में, विदेशी पर्यटकों के अधिक आगमन को परिलक्षित करते हुए यात्रा प्राप्तियों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, यूरोपीय संघ में, यात्रा निर्यात में 2 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि तुर्की में निर्यात अवरूद्ध हो गए। 2010 में अन्य वाणिज्यिक सेवाओं के सभी उप क्षेत्रों में समुत्थान एक समान नहीं था। जहां 2010 में विश्व का वित्तीय सेवाओं के निर्यातों में, आर्थिक संकट से उपजी तीव्र गिरावट के बाद 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं बीमा सेवा निर्यात अवरुद्ध हो गए। यूरोप के वित्तीय सेवा क्षेत्र, जो 2010 में वित्तीय सेवाओं के वैश्विक निर्यात का 49 प्रतिशत थे, वैश्विक संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए। इसने 2010 में उबरने का प्रयास किया जब अतिरिक्त यूरोपीय संघ के निर्यातों में 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और स्विटज़रलैण्ड में इसमें 2 प्रतिशत की गिरावट आई। 2010 में अमरीका के वित्तीय सेवा निर्यात 5 प्रतिशत बढ़े। लेकिन एशिया ने वित्तीय सेवाओं में जबर्दस्त समुत्थान का अनुभव किया जब सिंगापुर के निर्यातों में 31 प्रतिशत, हांगकांग के निर्यातों में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारत के निर्यातों में 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि जापान के निर्यातों में 25 प्रतिशत की कमी आई। कम्प्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात और रायल्टी एव लाइसेन्स शुल्क में क्रमश: 13 और 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि संचार सेवाओं के निर्यात में मूल्य के संदर्भ में 8 प्रतिशत की कमी आई जो कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट को परिलक्षित करती है। 2010 में लगभग सभी क्षेत्रों में निर्माण-निर्यातों में आर्थिक संकट के बाद कमी हो गई। 2010 में वैश्विक निर्माण-निर्यातों में 1 प्रतिशत की गिरावट इंगित करती है कि वैश्विक मंदी का प्रभाव इस क्षेत्र पर अभी भी छाया हुआ है। चीन को छोड़कर, सभी अग्रणी निर्यातकों ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है। यूरोपीय संघ जो निर्माण में विश्व का मुख्य क्षेत्र है, में निर्यातों में 7 प्रतिशत की कमी हुई, जापान में 10 प्रतिशत और रूस और कोरिया गणराज्य में 20 प्रतिशत की कमी हुई। चीन जबरदस्त विकास के चलते एकमात्र शीर्षस्थ निर्यातक था जहां कई अवसंरचना योजनाओं, खास तौर से अफ्रीका में चल रही परियोजनाओं के कारण निर्यात में 53 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

7.39 वर्ष 2010 में, भारत की वाणिज्यिक सेवाओं की तीनों प्रमुख श्रेणियों के व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी हुई। यहां तक कि संचार सेवाओं को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक सेवाओं में सभी उप क्षेत्रों में कम कीमतों और वैयक्तिक सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं के कारण निर्यात वृद्धि अच्छी रही। आयात पक्ष पर, केवल निर्माण सेवाओं ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है। भारत ने इनमें से अधिकतर सेवाओं में अपने स्थान में सुधार किया है, क्योंकि अन्य देश, खासतौर पर यूरोप ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है सारणी (7.12)। यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि सेवा व्यापार में, विशेष रूप से अधिकतर देशों में निर्माण सेवाओं में और यूरोपीय देशों में वित्तीय सेवाओं के मामले में 2008 की वैश्विक मंदी का असर छाया रहा। सेवा क्षेत्र में वर्तमान मंदी के संकेत इसमें अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।

भारत का सेवा व्यापार

भारत के सेवा निर्यात

7.40 एक दशक से भी अधिक समय तक भारत की विकास गाथा में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व रहा है। यह प्रभुत्व सेवाओं (प्राप्तियों) के निर्यात की प्रवृत्ति में भी स्पष्ट था जो 2000-01 से 2010-11 के दौरान 23.4 प्रतिशत पर बढ़े जबकि इसी अवधि में पण्य निर्यात में 18.6 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि हुई। 2009-10 में वैश्विक वित्तीय मंदी के कारण 9.4 प्रतिशत का संकुचन दर्ज करने के बाद, 2010-11 में सेवा निर्यात में 38.4 प्रतिशत का उछाल आया और ये बढ़कर 132.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। लेकिन निर्यात में वृद्धि 2010-11 के पूर्वार्ध के

सारणी 7.12 : सेवाओं में विश्व निर्यात/आयात में भारत का क्षेत्रवार रैंक एवं हिस्सा

सेवाएं		रैंक		हिस्सा		प्रतिशत परिवर्तन
		2009	2010	2005	2010	परिवर्तन 2010
परिवहन सेवाएं	निर्यात	13	10	1.0	1.7	21
	आयात	13	5	3.0	4.8	31
यात्रा सेवाएं	निर्यात	14	12	1.1	1.5	27
	आयात		...	...	...	...
अन्य वाणिज्यिक सेवाए	निर्यात	4	3	3.1	4.9	36
	आयात	8	5	1.9	3.5	66
संचार सेवाएं*	निर्यात	4	5	...	2.1	-5
	आयात	11	7	...	2.0	-7
निर्माण सेवाएं*	निर्यात	12	...	...	...	...
	आयात	13	10	...	1.6	-8
बीमा सेवाएं*	निर्यात	7	8	...	2.0	17
	आयात	7	7	...	3.1	24
वित्तीय सेवाएं*	निर्यात	7	7	...	1.5	64
	आयात	5	3	...	3.9	81
कम्प्यूटर एवं सूचना सेवाएं*	निर्यात	2	2	...	19.2	...
	आयात	4	7	...	2.6	12
अन्य व्यवसाय सेवाएं*	निर्यात	6	7	...	3.8	...
	आयात	6	6	...	3.3	89
वैयक्तिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं*	निर्यात	5	8	...	1.3	-28
	आयात	12	...	...	...	...

स्रोत : डब्ल्यूटीओ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2011 से संकलित।
टिप्पणी : *डाटा 2009 से संबंधित है; डब्ल्यूटीओ सचिवालय के अनुमान।

32.7 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 2011-12 के पूर्वार्ध में 17.1 प्रतिशत रह गई (सारणी 7.13)।

7.41 जहां 2010-11 के पूर्वार्ध के मुकाबले 2011-12 के पूर्वार्ध में यात्रा, परिवहन और बीमा सेवाओं के निर्यात में वृद्धि अधिक

सारणी 7.13 : भारत का सेवा निर्यात

क्र. सं.	वस्तु समूह	मूल्य (अमरीकी बिलियन डालर)	हिस्सा (प्रतिशत)				सीएजीआर	विकास दर*			
					अप्रैल. सितम्बर		2000.01 से			अप्रैल. सितम्बर	
		2010-11	2000-01	2010-11	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
1.	यात्रा	15.3	21.5	11.5	10.9	12.9	15.3	8.9	28.8	26.2	38.7
2.	परिवहन	14.3	12.6	10.7	11.0	12.8	23.8	-1.2	27.7	26.5	36.1
3.	बीमा	1.9	1.7	1.5	1.5	1.7	23.1	11.9	22.5	10.2	38.8
4.	जीएनआईई	0.5	4.0	0.4	0.4	0.4	-6.2	13.4	21.3	9.5	30.6
5.	विविध	100.9	60.3	75.9	76.2	72.1	30.4	-12.4	42.1	35.3	10.7
	क) साफ्टवेयर सेवाएं	55.5	39.0	41.7	42.7	45.2	28.2	7.4	11.6	11.6	24.1
	ख) गैर साफ्टवेयर सेवाएं जिसका	45.4	21.3	34.2	33.5	26.9	33.8	-40.3	113.0	85.6	-6.3
	i) व्यवसाय सेवाएं	24.1	2.1	18.1	18.5	15.9	65.3	-39.4	112.4	111.4	0.3
	ii) वित्तीय सेवाएं	6.5	2.1	4.9	5.2	4.2	37.5	-16.6	76.3	64.9	-6.7
	iii) संचार सेवाएं	1.6	7.0	1.2	1.3	1.1	9.2	-46.6	27.2	2.3	1.1
	कुल सेवा निर्यात	**132.9**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**26.4**	**-9.4**	**38.4**	**32.7**	**17.1**

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं
टिप्पणी: * वृद्धि दर अमरीकी डालर में
जीएनआईई = सरकार अन्यत्र शामिल नहीं

थी, 2011-12 के पूर्वार्ध में सेवाओं के निर्यात में समग्र वृद्धि में हुई कमी विविध सेवाओं, जो कुल सेवा निर्यात का लगभग 72 प्रतिशत बैठता है, के निर्यात में कम वृद्धि (10.7 प्रतिशत) होने के कारण थी। विविध सेवाओं की श्रेणी में ही, गैर सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में-6.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि रही। कारोबारी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, जो गैर-साफ्टवेयर सेवा का मुख्य घटक है, ने निर्यात वृद्धि में तीव्र गिरावट दर्ज की और 2010-11 के पूर्वार्ध में 111.4 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 के पूर्वार्ध में 0.3 प्रतिशत रह गया जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कारोबारी क्रियाकलाप में मंदी दर्शाता है। वित्तीय सेवाओं के निर्यात में 2010-11 के पूर्वार्ध में 64.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2011-12 के पूर्वार्ध में 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई जो एक बार फिर यूरोपीय देशों में छाई वर्तमान वित्तीय मंदी के प्रभाव का प्रतिबिम्ब है। तथापि, सॉफ्टवेयर निर्यात जो कुल सेवा निर्यातों का लगभग 45 प्रतिशत बैठते हैं, 30.8 बिलियन अमरीकी डालर पर वृद्धिकारी रुख पर बने रहे और 2011-12 के पूर्वार्ध में इसमें 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नैसकॉम के अनुसार, सॉफ्टवेयर निर्यातों में 2012-13 में निर्यातों में 11-14 प्रतिशत की दर पर बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। भविष्य में देखें तो, यदि यूरो जोन के ऋण संकट का समाधान नहीं होता और अन्य विकसित देशों पर इसका असर फैलता है तो अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों की कंपनियां अपने सूचना प्रौद्योगिकी बजट में कटौती कर सकती हैं, जिसका असर भारत के भावी सॉफ्टवेयर निर्यात पर पड़ सकता है। इसी तरह, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाकलापों के कमजोर पड़ने से कारोबारी और वित्तीय सेवाओं में और गिरावट हो सकती है जैसाकि 2008-09 की चौथी तिमाही से 2009-10 की चौथी तिमाही में देखा गया है।

भारत का सेवा-आयात

7.42 सेवाओं की आयात वृद्धि में 2010-11 में उछाल आया जब 40 प्रतिशत की दर पर विकास हुआ। लेकिन 2011-12 के पूर्वार्ध में, इसमें 2010-11 के पूर्वार्ध के 48.3 प्रतिशत की तुलना में केवल 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवाओं के आयात की वृद्धि में आई गिरावट मुख्यत: 2011-12 के पूर्वार्ध में विविध सेवाओं के अपेक्षाकृत कम आयातों के कारण थी। विविध सेवाओं में ही, सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाओं में 2011-12 के पूर्वार्ध में क्रमश: 47.5 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि 2010-11 के पूर्वार्ध में क्रमश: 39.9 प्रतिशत और 62.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2011-12 के पूर्वार्ध में, वित्तीय और परिवहन सेवाओं की आयात वृद्धि कम होकर क्रमश: 21.1 प्रतिशत और 14.5 प्रतिशत रह गई। तथापि, यात्रा सेवाओं की आयात वृद्धि दोगुने से अधिक होकर 39.7 प्रतिशत हो गई (सारणी 7.14)।

सेवाओं में भारत का व्यापार शेष

7.43 भारत के सेवा निर्यातों के खाते पर अधिशेष में हुई निरन्तर वृद्धि हालिया वर्षों में पण्य खाते पर व्यापार घाटे के अधिकांश हिस्से के वित्तपोषण हेतु अनुकूल कारक रही है। 2005-06 से 2009-10 तक, सेवा निर्यातों के अधिशेष से पण्य व्यापार घाटे के औसतन लगभग 41 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ। निवल सेवा अधिशेष जो पिछले वर्षों में बढ़ रहा था, ने 2009-10 में कमी

सारणी 7.14 : भारत का सेवा आयात

क्र. सं.	वस्तु समूह	मूल्य (अमरीकी बिलियन डालर)	हिस्सा (प्रतिशत)				सीएजीआर	विकास दर *			
					अप्रैल.. सितम्बर		2000.01 से			अप्रैल.. सितम्बर	
		2010-11	2000-01	2010-11	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
1.	यात्रा	11.1	19.2	13.2	13.8	19.1	16.4	-0.9	18.9	15.1	39.7
2.	परिवहन	13.9	24.4	16.5	18.2	20.7	17.4	-6.9	16.3	33.2	14.5
3.	बीमा	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	22.5	13.7	8.9	6.3	3.6
4.	जीएनआईई	0.8	2.2	1.0	1.0	1.0	12.1	-33.8	56.2	49.4	9.2
5.	विविध	56.9	52.6	67.6	65.1	57.2	17.5	32.5	53.9	65.5	-11.2
	क) साफ्टवेयर सेवाएं	2.2	4.1	2.6	3.2	1.6	20.1	-42.7	49.5	39.9	-47.5
	ख) गैर साफ्टवेयर सेवाएं जिसका	54.7	48.6	65.0	61.9	55.6	17.3	40.1	54.1	67.1	-9.4
	i) व्यवसाय सेवाएं	27.8	7.0	33.0	35.2	34.3	40.3	17.8	53.8	62.6	-1.7
	ii) वित्तीय सेवाएं	7.5	13.5	8.9	9.1	10.9	5.2	56.9	61.2	68.0	21.1
	iii) संचार सेवाएं	1.2	0.9	1.4	1.4	2.0	30.8	24.7	-15.0	-14.2	42.8
	कुल सेवा आयात	84.1	100.0	100.0	100.0	100.0	17.2	15.3	40.0	48.3	1.0

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं

टिप्पणी: * वृद्धि दर अमरीकी डालर में

सारणी 7.15 : भारत का निर्यात, आयात और सेवाओं में व्यापार शेष

(बिलियन अमरीकी डालर)

	निर्यात	आयात	शेष
2000-1	16.3	14.6	1.7
2001-2	17.1	13.8	3.3
2002-3	20.8	17.1	3.6
2003-4	26.9	16.7	10.1
2004-5	43.2	27.8	15.4
2005-6	57.7	34.5	23.2
2006-7	73.8	44.3	29.5
2007-8	90.3	51.5	38.9
2008-9	106.0	52.0	53.9
2009-10	96.0	60.0	36.0
2010-11	132.9	84.1	48.8
2010-11 (अप्रैल-सित.)	58.1	36.6	21.5
2011-12 (अप्रैल-सित.)	68.0	36.9	31.1

स्रोत : आरबीआई डाटा के आंकड़ों से संकलित।

दर्शाई जब वैश्विक आर्थिक संकट के कारण सेवा निर्यात घट रहा था किन्तु सेवा आयात बढ़ रहा था। तथापि, 2010-11 में निवल सेवा अधिशेष फिर बढ़ गया और 48.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया था। 2011-12 के पूर्वार्ध के दौरान निवल सेवाओं में 31.1 बिलियन अमरीकी डालर का अधिशेष दर्ज किया गया जो 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान दर्ज किए गए अधिशेष से 44.7 प्रतिशत अधिक है (सारणी 7.15)। भविष्य की बात करें तो, सेवाओं का निर्यात घट जाने के जोखिम को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कतिपय कमजोरियां फिर से उभरी हैं, विशेषकर यूरो जोन में आया संकट और अमरीकी अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी।

व्यापार नीति

व्यापार नीति संबंधी हालिया उपाय

7.44 सरकार द्वारा 13 अक्तूबर 2011 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के वार्षिक अनुपूरक विवरण में व्यापार नीति संबंधी कई उपायों की घोषणा की गई थी (बॉक्स 7.3 देखें)। इस वर्ष के दौरान सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2011-12 में और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक और ऋण संबंधी नीतियों में भी कई उपाय किए गए थे, जो इस प्रकार हैं:

बजट से संबंधित उपाय

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरन्तर बनी हुई अनिश्चितताओं को देखते हुए सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत बनाई रखी गई।
- कृषि संबंधी कार्य में प्रयोग किए जाने वाली विनिर्दिष्ट मशीनरी और ऐसी मशीनरी के पुर्जों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत के रियायती दर पर रखा गया ताकि इनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।
- तेल रहित चावल की खली को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई। इसी के साथ, इसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया।
- निम्नलिखित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती इस प्रकार की गई है—कच्चे रेशम (जिसे धागे का रूप न दिया गया हो) पर 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; कतिपय वस्त्र मध्यवर्तियों तथा रसायन, लौह अयस्क, एवं कागज की निविष्टियों पर 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत; कतिपय तकनीकी रेशे और धागे के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कतिपय निविष्टियों पर 7.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत; कच्चे पिस्ता और अगरबत्ती हेतु बांस पर 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत; होम्योपैथिक दवाइयों के विनिर्माण हेतु दुग्धशर्करा पर 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत।
- स्टेनलैस स्टील की स्क्रैप को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रखा गया;
- विशिष्ट इलेक्ट्रानिक पुर्जों, जिन्हें बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है, के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री की सूची में विस्तार किया गया;
- हाइब्रिड वाहनों विशिष्ट पुर्जों को बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक शुल्क (सीएडी) से पूरी छूट दी गई है।
- प्रशीतन श्रृंखला की अवसंरचना हेतु वातानुकूलन उपस्कर और प्रशीतन पैनलों तथा कन्वेयर बेल्ट और पूर्व-चर्मशोधन हेतु एंजाइम आधारित तैयारियों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- सीमा शुल्क प्रशासन का विश्वास पर आधारित सीमा शुल्क व्यापार भागीदारी के नए युग में प्रवेश करने के लिए आधुनिकीकरण और कार्गो की शीघ्र निकासी के लिए सीमा शुल्क में स्व-मूल्यांकन।
- मेगा क्लस्टर स्कीम में चर्म उत्पादों को शामिल किया गया।
- सभी प्रकार के लौह अयस्कों पर यथा मूल्य 20 प्रतिशत का एकीकृत निर्यात शुल्क लगाया गया।

ऋण से संबंधित उपाय (व्यापार वित्त भाग का पैरा 7.8 से 7.10 भी देखें)

- हस्तशिल्प, हथकरघा, कारपेट और एसएमई क्षेत्रकों में रूपया निर्यात ऋण पर 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता पुन: शुरू की गई।
- लागत (अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज लागत) को घटाने के लिए अतिदेय निर्यात बिलों वाले निर्यातकों को उनके रूपया संबंधी संसाधनों से अपना अतिदेय पश्च-लदान रूपया निर्यात-ऋण समाप्त करने की अनुमति दी गई।

बॉक्स 7.3 : 2011 में किए गए विदेश व्यापार नीति संबंधी उपाय

व्यापार संबंधी और सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

व्यापार नीति संबंधी उपाय

- शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) स्कीम 30.09.2011 से समाप्त की गई थी। चूंकि शुल्क वापसी स्कीम पहले से मौजूद थी, पूर्ववर्ती डीईपीबी उत्पाद 01-10-2011 से शुल्क वापसी अनुसूची (डीडीएस) 2011-12 में समाहित किए गए थे। उन पूर्ववर्ती डीईपीबी उत्पादों के संबंध में लगभग 1100 अतिरिक्त प्रविष्टियां की गई थीं जिन्हें डीडीएस में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किया गया था। शुल्क वापसी की उचित दरें डीडीएस में दी गई थीं। ये एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के दायरे में है। 3 प्रतिशत से अधिक की शुल्क वापसी दरों वाली कई निर्यात वस्तुओं पर शुल्क वापसी की अधिकतम सीमा लगाई गई है।
- इंजीनियरी, औषध निर्माण और रसायन क्षेत्रकों के 49 उत्पादों को शामिल करते हुए फोकस प्रॉडक्ट स्कीम में ही स्पेशल बोनस बेनेफिट स्कीम शुरू की गई थी ताकि 1.10.2011 से 31.3.2012 तक के 6 महीनों के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत के दर पर विशेष सहायता मुहैया की जा सके।
- 41 देशों (12 लैटिन अमरीकी क्षेत्र से, 22 अफ्रीकी क्षेत्र से और 7 सीआईएस क्षेत्र से) को निर्यात किए जाने के लिए फोकस मार्केट स्कीम में ही स्पेशल फोकस मार्केट स्कीम इस दृष्टि से शुरू की गई थी कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। इस स्कीम में इन देशों को निर्यात किए जाने पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट दिया जाता है जो अन्ततः निर्यात के एफओबी मूल्य के 4 प्रतिशत की दर से कुल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप बैठता है।
- परिधान के निर्यात में सहायता के लिए, आईटीसीएचएस वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के तहत शामिल की गई सभी मदों के लिए एमएलएफपीएस दी गई जिससे उन्हें 2011-12 के दौरान यूएसए और ईयू को इन उत्पादों का निर्यात किए जाने पर निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र होने की हकदारी मिलती है।
- मुख्यतः रसायन/औषध निर्मिति, वस्त्र, हस्तशिल्प, इंजीनियरी तथा इलैक्ट्रानिक क्षेत्रकों की लगभग 130 अतिरिक्त मदें एफपीएस में शामिल की गई हैं जिन्हें 1-4-2011 से किए गए निर्यातों के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप मिलेगा।
- विशिष्ट देशों के लिए नई मदें शामिल करने और निर्यात के एफओबी मूल्य की 2 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पाने के पात्र होने के लिए एमएलएफपीएस के तहत मदों की सूची विस्तृत की गई है। इनमें तुर्की को दिए जाने वाले 1800 सीसी क्षमता के कृषि ट्रैक्टर, ब्राजील, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और मिस्त्र को दिए जाने वाली चीनी मशीनरी और उच्च-दाब वाले बॉयलर शामिल हैं। मुद्रण स्याही, लेखन स्याही आदि के लिए इस स्कीम में भी सभी मौजूदा एमएलएफपीएस देशों को शामिल किया गया है।
- स्टेट्स होल्डर्स इन्सेंटिव स्क्रिप 2012-13 के लिए बढ़ा दी गई है।
- कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद, समुद्री उत्पादों के लिए भुवनेश्वर तथा बांस और बेंत के उत्पादों के लिए अगरतला को निर्यात उत्कृष्टता के शहरों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

व्यापार सरलीकरण संबंधी उपायः

- लगभग सभी स्कीमों में विभिन्न अनुज्ञप्तियों के लिए ईडीआई मोड के तहत आवेदन करना अधिदेशित किया गया है।
- पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) संबंधी आंकड़े अपलोड करने के लिए 37 ईपीसी में से 24 ने डीजीएफटी की वेबसाइट पर पंजीकरण किया है। इससे आरसीएमसी की मुद्रित प्रतिलिपियां बार-बार जमा करने से बचा जा सकेगा, अतिरेक खत्म होगा और कारोबार लागत कम होगी।
- डीजीएफटी के प्रयोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (ईएफटी) की सुविधा हेतु मौजूदा 11 बैंकों के अलावा दो अतिरिक्त बैंक नामशः (i) बैंक ऑफ बड़ौदा (ii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है।
- अगस्त, 2010 में अग्रिम अनुज्ञप्तिकरण तथा ईपीसीजी आवेदनों के लिए एक ऑफ लाइन डाटा एंट्री मॉडयूल प्रदान किया गया था ताकि निर्यातकों को आवेदन प्रस्तुत करने में आजादी दी जा सके और ऑन लाइन सर्वर समय कम किया जा सके जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी और लागत कम होगी।
- 1.1.2011 से आयातक निर्यातक संहिता (आईईसी) अनुप्रयोग के 'ऑन लाइन' प्रस्तुतीकरण और प्रक्रियान्वयन की शुरुआत की गई है। ऑन लाइन पैन वैधीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिए पैन डाटाबेस के साथ ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण और निर्गम प्रणाली के लिंकेज को समेकित किया जा रहा है।
- अब तक अग्रिम अनुज्ञप्तिकरण, ईपीसीजी और शुल्क मुक्त आयात अनुज्ञप्तिकरण (डीएफआईए) के लिए सीमा शुल्क विभाग के साथ संदेश के आदान-प्रदान को क्रियान्वित किया गया है। संदेश आदान प्रदान की सुविधा अन्य स्कीमों अर्थात वार्षिक अग्रिम अनुज्ञप्तिकरण, वार्षिक ईपीसीजी, एसएफआईएस और एसएचआईएस को भी दी जा रही है।
- नीति संबंधी छूट समिति (पीआरसी) द्वारा मामलों का 'ऑन लाइन' प्रस्तुतीकरण करने, इसके प्रक्रियान्वयन और उसके बाद स्टैटस ट्रैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित की गई है।
- अग्रिम अनुज्ञप्तिकरण और ईपीसीजी अनुज्ञप्तिकरण के लिए एक वेब आधारित ट्रैकिंग और मानीटरिंग पैकेज डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, निर्यात बाध्यता की मानीटरिंग के लिए सभी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरणों (आरएलए) के लिए इसकी सुविधा उपलब्ध है।
- डीजीएफटी भारत में भारत सरकार का प्रथम डिजिटल हस्ताक्षर समर्थ विभाग भी बना है, जिसने उच्च स्तरीय एनक्रिप्टेड 2048 बिट डिजिटल हस्ताक्षर की शुरूआत की है। 2048 बिट डीएससी सभी कार्यालयों को जारी किया गया है।

- निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण सुविधा की सीमा 15 प्रतिशत के संकट-पूर्व स्तर पर ही रखी गई।

मुद्रास्फीति नियंत्रण से संबंधित उपाय

- सभी आयातित कच्ची चीनी और सफेद/परिष्कृत चीनी के संबंध में लेवी की बाध्यता हटाई गई।
- खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन-आधारित तेल छोड़कर) और दालों (प्रति वर्ष अधिकतम 10,000 टन तक काबुली चना और जैविक दालों को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
- खाद्य तेलों के टैरिफ दर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
- कुछ समय के लिए गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
- 5 कि॰ग्रा॰ तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों का 10,000 टन की सीमा के अध्यधीन निर्यात।
- दूध पाउडर (जिसमें वसारहित दूध पाउडर, वसायुक्त दूध पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्ध खाद्य शामिल हैं), छेना और छेना से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
- जब भी आवश्यक हुआ, कुछ समयावधि के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के तंत्र के जरिए आंका गया।
- चावल, गेहूं, प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) हेतु आयात शुल्क घटाकर शून्य किया गया और परिष्कृत तथा हाइड्रोजनित तेलों और खाद्य तेलों का आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को टैरिफ रेट कोटा के तहत शून्य शुल्क पर 50,000 टन वसारहित दूध पाउडर और वसायुक्त दूध पाउडर तथा 15,000 मिलियन टन मक्खन, मक्खन तेल, एवं शुष्क दुग्ध वसा आयात करने की अनुमति दी गई।
- चीनी मिलों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शुल्क मुक्त कच्ची चीनी का आयात करने की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा कार्य के आधार पर निजी व्यापार को दी गई।
- राज्य व्यापार निगम (एसटीसी)/खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी)/परियोजना और उपस्कर निगम (पीईसी) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) को आरंभिक रूप से 1 मिलियन टन की अधिकतम सीमा के साथ सफेद/परिष्कृत चीनी का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई। बाद में, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और निजी व्यापार हेतु भी मात्रा पर अधिकतम सीमा लगाए बिना शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई थी।

राज्य-वार निर्यात संवर्धन की नीति

7.45 वस्तु-निर्यातों के उद्गम के राज्य से संबंधित आंकड़ों के अनुसार दो राज्य नामशः गुजरात और महाराष्ट्र का भारत से किए जाने वाले निर्यातों में 46 प्रतिशत हिस्सा है। यदि 5 प्रतिशत से अधिक के हिस्से वाले अगले तीन राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को शीर्ष दो राज्यों के साथ मिला दिया जाए तो शीर्ष पांच राज्यों का हिस्सा 65.7 प्रतिशत हो जाएगा। 2010-11 में, सभी राज्यों से हुए निर्यातों की वृद्धि जबर्दस्त रही थी। कर्नाटक सरकार द्वारा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कारण अयस्क के निर्यात में गिरावट आने से केवल गोवा राज्य की निर्यात वृद्धि ऋणात्मक रही थी। ओडिशा द्वारा उच्च निर्यात वृद्धि दर्ज की गई थी जिसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात का स्थान था। 2011-12 के पूर्वार्ध में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के मामले में जबर्दस्त निर्यात वृद्धि हुई थी (सारणी 7.16)।

7.46 सारणी 7.16 में दिया गया राज्य-वार निर्यात केवल निर्देशात्मक है क्योंकि इन आंकड़ों में कई खामियां हैं। ये खामियां इस प्रकार हैं—ये आंकड़े सीमा शुल्क कार्यालय की रिपोर्टिंग के अनुसार संकलित किए जाते हैं तथा डीजीसीआई एण्ड एस में इनका कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है। निर्यातक द्वारा एक जहाज लदान बिल में केवल एक ही उद्गम राज्य का कोड दिया जा सकता है। एक से अधिक राज्य से भेजे जाने वाली मदों के बहु बीजकों वाले जहाज लदान के बिलों के मामले में, पृथक-पृथक प्रविष्टियां करने का प्रावधान नहीं है। सीमा शुल्क दैनिक व्यापार विवरण (डीटीआर) में उद्गम राज्य की रिपोर्टिंग न करने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं और निर्यातक की प्रवृत्ति उस राज्य को रिपोर्ट करने की होती है जिसका वह निवासी है उस राज्य को जिसमें पत्तन है (जहां से निर्यात किया गया)/वस्तुओं के वास्तविक उद्गम राज्य के स्थान पर उन विशेष वस्तुओं के उद्गम के राज्य के रूप में जहां से वस्तुओं की 'अधिप्राप्ति' की है। ऐसे गैर-विनिर्माता निर्यातकों के मामले में यह समस्या अधिक गंभीर है जो वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में जानकारी रखने की बजाय केवल अधि प्राप्ति के स्थान के बारे में जानते हैं। आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये खामियां दूर किए जाने की आवश्यकता है।

7.47 निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात अवसंरचना तथा सहबद्ध कार्यकलाप संवर्धन (एसाइड) योजना हेतु राज्यों को दिए जाने वाली सहायता के तहत परिव्यय बढ़ाकर 3,793 करोड़ रूपये किया गया था। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए आवंटन क्रमशः 569 करोड़ रुपये, 570 करोड़ रुपये, 570 करोड़ रुपये, 662.98 करोड़ रुपये और 850.96 करोड़ रुपये था। 'एसाइड' के राज्य घटक के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन यह दर्शाता है कि 2011-12 में आवंटन के संदर्भ में शीर्ष छः राज्य हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में महाराष्ट्र का हिस्सा कम हो

सारणी 7.16 : भारत के शीर्ष 15 राज्यों निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	(अप्रैल-सित.) 2010-11	(अप्रैल-सित.) 2011-12	हिस्सा % 2010-11	वृद्धि दर (%) 2010-11	वृद्धि दर (%) 2011-12 (अप्रैल-सित.)
1.	गुजरात	38775	61694	24647	31246	24.6	59.1	26.8
2.	महाराष्ट्र	43356	53788	23394	33140	21.4	24.1	41.7
3.	तमिलनाडु	16085	23378	8541	14179	9.3	45.3	66.0
4.	कर्नाटक	9093	13603	5006	8509	5.4	49.6	70.0
5.	आंध्र प्रदेश	8559	12567	6524	8533	5.0	46.8	30.8
6.	हरियाणा	5679	8584	3574	4240	3.4	51.2	18.6
7.	उत्तर प्रदेश	5524	8208	3849	6529	3.3	48.6	69.6
8.	पश्चिम बंगाल	4197	7111	2886	3970	2.8	69.4	37.6
9.	ओडिशा	3230	6990	2698	2075	2.8	116.4	-23.1
10.	केरल	5843	6547	2646	3717	2.6	12.1	40.5
11.	दिल्ली	5187	6051	2907	4038	2.4	16.7	38.9
12.	राजस्थान	3339	5214	1749	2626	2.1	56.2	50.2
13.	पंजाब	2732	4099	1904	2645	1.6	50.0	38.9
14.	मध्य प्रदेश	2357	3112	1147	1637	1.2	32.0	42.7
15.	गोवा	2481	1642	1074	774	0.7	-33.8	-27.9
	कुल निर्यात	**178751**	**251136**	**105241**	**147949**	**100.0**	**40.5**	**40.6**

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता के आंकड़ों से परिकलित।

गया है जबकि तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम ही एकमात्र राज्य है जिसका उल्लेखनीय हिस्सा है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़)

7.48 फरवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) अधिनियम और नियमावली अधिसूचित किए जाने के बाद की लगभग पांच वर्षों की छोटी सी अवधि में 583 सेज़ स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन दिया जा चुका है जिनमें से 380 सेज अधि सूचित किए जा चुके हैं। समग्र रूप से सेज में 815308 व्यक्तियों को दिए गए कुल रोजगार में से, फरवरी 2006 जब सेज़ अधिनियम प्रवृत्त हुआ था, के बाद पैदा किया गया उत्तरोत्तर रोजगार 680609 व्यक्ति था। यह अवसंरचना कार्यकलापों के लिए डेवलपर द्वारा सृजित रोजगार के 10 लाख मानव दिवसों के अलावा है। सेज़ से किया गया वास्तविक निर्यात 2009-10 में 2,20,711.39 करोड़ रूपये से बढ़कर 2010-11 में 3,15,867.85 करोड़ रुपये हो गया जो रुपये के संदर्भ में 43.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले आठ वर्षों (2003-04 से 2010-11 तक) में निर्यात की समग्र वृद्धि 2180 प्रतिशत रही है। 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति अर्थात् चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में सेज से किया गया कुल वास्तविक निर्यात 260972.9 करोड़ रुपये राशि का रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में किए गए निर्यात में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 31 दिसम्बर 2011 तक सेज़ में किया गया कुल निवेश लगभग 2,49,630.8 करोड़ रुपये है जिसमें अधिसूचित किए गए नए सेज़ों में हुआ 2,31,160 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। सेज़ अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, सेज़ में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। कुल 154 संघ निर्यात कर रहे हैं जिनमें से 88 आईटी/आईटीईएस, 17 बहु-उत्पाद और 49 अन्य क्षेत्र-विशिष्ट सेज़ हैं। इन सेज़ों में कुल यूनिटों की संख्या 3,400 है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में व्यापार संवर्धन और अन्य पहलें

7.49 वाणिज्य विभाग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर क्षेत्र से होने वाले निर्यात का संवर्धन करने में मदद करना है। निर्यात विकास निधि से (ईडीएफ) उन क्रियाकलापों को सहायता प्रदान की जाती है जो इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात से जुड़े हैं और ईडीएफ से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। अब तक (24 फरवरी 2012 तक) ईडीएफ-एनईआर के तहत 67.78 करोड़ रुपये राशि की 68 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ईडीएफ-एनईआर के तहत अनुमोदित/विचाराधीन प्रमुख परियोजनाओं में पुष्पोत्पादन की ये मदें शामिल हैं—एंथूरियम, जरबेरा, कट फ्लॉवर, ऑर्किड, और गुलाब की खेती; पैशन फ्रूट, संतरा, किवी, अदरक, हल्दी, कैण्ड मशरूम, सफेद मुसली, बड़ी इलायची की खेती और प्रसंस्करण;

मधुमक्खी पालन और शहद का प्रसंस्करण; खाद्य जांच प्रयोगशालाओं, सीमा व्यापार स्थलों आदि का अवसंरचना विकास; हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशम; रबड़-काष्ठ आधारित दरवाजों का विनिर्माण तथा परामर्श, मानीटरिंग और निर्यात संबंधी जागरूकता पर कार्यशालाएं।

आकस्मिक व्यापार नीति और टैरिफ-भिन्न उपाय (एनटीएम)

7.50 सभी देशों द्वारा शुरू किए गए डंपिग रोधी अन्वेषण के मामले जो वैश्विक आर्थिक संकट के चलते वर्ष 2008 में बढ़ गये थे, 2009 में मामूली से कम होकर 209 मामले रह गए और 2010 तथा 2011 के पूर्वार्ध में काफ़ी कम होकर क्रमश: मात्र 170 और 68 मामले रह गए (सारणी 7.17)। भारत पिछले दशक में शुरू किए गए अन्वेषणों के संदर्भ में डम्पिंग रोधी उपायों का अग्रणी प्रयोक्ता रहा है सिवाय 2004 के जब इस सूची में यूरोपीय संघ पहले स्थान पर था और इसके बाद चीन और इसके बाद अमरीका का स्थान था। वैश्विक घटनाक्रमों की तर्ज पर भारत की डम्पिंग रोधी पहलें 2008 में बढ़कर 55 हो गईं, 2009 में कम होकर 31 रह गईं किंतु फिर से बढ़कर 2010 में 41 हो गई। ब्राजील 2010 में 37 पहलों के साथ दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2010 के पूर्वार्ध में ब्राजील ने 11 डम्पिंग रोधी पहलों के साथ 10 पहलों वाले भारत को दूसरे स्थान पर खिसका दिया।

7.51 2011-12 (31 दिसम्बर 2011 तक) के दौरान डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा 6 नए डंपिंग रोधी अन्वेषणों की शुरूआत की गई है। इनमें ये उत्पाद शामिल हैं-थैलिक एनहाइड्राईड, ग्राइंडिग मीडिया बॉल्स, डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट, 9.5 मिमी, 12.5 मिमी और 15 मिमी (+/-0.6मिमी) के साधारण जिप्सम बोर्ड, कोलाईन क्लोराइड और राल अथवा जैविक वस्तु की परत वाले काष्ठ अथवा 6 मिमी के कम की मोटाई वाले लिग्नस फाइबर बोर्ड सिवाय इन्सूलेशन बोर्ड, लैमिनेटेड फाइबर बोर्ड और उन बोर्डों के जिन पर रेजिन अथवा जैविक वस्तुओं का लेप नहीं होता। इन अन्वेषणों में ये देश संलिप्त हैं-कोरिया आर पी, चीनी थाइपेई (थाईवान), इजराइल, ईरान, थाईलैंड, चीन पी आर, जापान, इंडोनेशिया, यूएई, यूरोपीय संघ, मलेशिया और श्रीलंका।

7.52 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल में छाई अनिश्चितता से आने वाले महीनों में देशों द्वारा किए जाने वाले डंपिंग रोधी उपायों में बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे अधिक डंपिंग रोधी उपाय किए जाने के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनावश्यक आलोचना होती रही है, जो एनटीएम का स्पष्ट प्रकार है, हालांकि इन वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से पहले आयात का मूल्य नगण्य है। शुल्क लागू किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के वर्ष में अर्थात 2009-10 में उन 12 मदों जिन पर 2010-11 (अप्रैल-मार्च) में डंपिंग रोधी शुल्क लागू किए गए थे, के संबंध में भारत के कुल आयातों में लक्षित देशों से किए गए आयात का हिस्सा केवल 0.6 प्रतिशत है। 2010-11 में यह 0.4 प्रतिशत था (सारणी 7.18) यह केवल एक अकेली मद अर्थात चीन से सिंकरोनस डिजिटल हाईरारकी ट्रांसमिशन उपस्कर के आयात के कारण था जिसका लक्षित देशों से किए गए इन मदों के आयातों का 66 प्रतिशत हिस्सा है।

7.53 यद्यपि भारत की डंपिंग-रोधी नीति डंपिंग के वास्तविक मामलों को नियंत्रित करने के लिए निदेशित है, फिर भी अनावश्यक अन्तरराष्ट्रीय आलोचना से बचने के लिए इस नीति को और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। इस बीच खुली भारतीय सीमाओं के जरिए बेकार अथवा तस्करी के सामान के सस्ते आयात से घरेलू अर्थव्यवस्था का पर्याप्त संरक्षण किए जाने की जरूरत होगी। अन्य देशों के तुलनात्मक मूल्य आंकड़ों को उजागर करके भारत के बड़ी संख्या में डंपिंग के मामलों को लेकर की गई अतिशयोक्ति को दूर करने की आवश्यकता है।

सारणी 7.17 : डंपिंग रोधी उपायों के शीर्ष दस प्रयोक्ताओं द्वारा शुरू किए गए अन्वेषण 1995-2011

देश	1995	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	1995-2011*
भारत	6	79	81	46	21	28	35	47	55	31	41	10	647
अमरीका	14	77	35	37	26	12	8	28	16	20	3	9	452
यूरोपीय संघ	33	28	20	7	30	24	35	9	19	15	15	8	428
अर्जेन्टीना	27	28	14	1	12	12	11	8	19	28	14	4	288
ब्राजील	5	17	8	4	8	6	12	13	23	9	37	11	227
आस्ट्रेलिया	5	24	16	8	9	7	11	2	6	9	7	2	219
दक्षिण अफ्रीका	16	6	4	8	6	23	3	5	3	3	0	1	213
चीन	0	14	30	22	27	24	10	4	14	17	8	0	186
कनाडा	11	25	5	15	11	1	7	1	3	6	2	0	153
तुर्की	0	15	18	11	25	12	8	6	23	6	2	1	147
सभी देश	157	372	315	234	220	201	204	165	213	209	170	68	3922

स्रोत: डब्ल्यूटीओ *जून 2011 तक

सारणी 7.18 : भारत द्वारा 2010-11 (अप्रैल-मार्च) में लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क

मदों की सं.	मामलों की सं.	शामिल देशों की सं.	लक्षित देशों से आयातित मदों का मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)		सभी देशों से आयातित मदों का मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	
			2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
12	19	10	1767	1304	7226	6392
			(0.6)	(0.4)	(2.5)	(1.7)

स्रोत : डंपिंगरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से परिकलित।
टिप्पणी: भारत के कुल आयात में प्रतिशत कोष्ठकों में दिया गया है।

विश्व व्यापार संगठन वार्ताएं और भारत

व्यापार वार्ताएं

7.54 वर्ष 2008 के बाद से डब्ल्यूटीओ में व्यापार वार्ताओं के दोहा चरण में बहुत कम प्रगति हुई। वर्ष 2009 और 2010 के दौरान चर्चाएं जारी रहीं लेकिन इन वार्ताओं में किसी भी महत्वपूर्ण मसले पर कोई हल नहीं निकला। मुख्य वार्ताकारी मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण का सारांश (बाक्स 7.4) में दिया गया है तथापि, यह विषय लगभग प्रत्येक बड़ी अन्तरराष्ट्रीय बैठक के एजेण्डों में शामिल रहा और दोहा चरण के समापन हेतु राजनीतिक समर्थन पर जबरदस्त सहमति थी। मार्च और अप्रैल 2011 में विभिन्न स्वरूपों में जिनेवा में चर्चाएं जारी रहीं। वार्ताओं के प्रत्येक क्षेत्र की रिपोर्ट 21 अप्रैल 2011 को जारी की गई। इन दस्तावेजों में ''दोहा डेवलपमेंट एजेण्डा'' में शामिल प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित वार्ताओं की प्रास्थिति पर नज़र डाली गई। हालांकि उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति का संकेत दिया, किन्तु उन्होंने कई मुद्दों पर व्याप्त बड़े अन्तर का भी जिक्र किया।

7.55 इसके बाद वार्ताओं का केंद्र दिसंबर 2011 में होने वाले डब्ल्यूटीओ के आठवें मंत्रालयी सम्मेलन के लिए समय से शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के तौर पर तय करने के लिए कुछ मुद्दों के चयन की संभावना पर चला गया। इसकी शुरूआत अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण मसलों को चुनने के प्रयास के साथ हुई। हालांकि इन प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली और ये न केवल निष्फल ही सिद्ध हुए बल्कि सदस्यों में बहुत मतभेद भी पैदा हो गए। सदस्य शामिल किए जाने वाले मसलों पर सहमत नहीं हो सके और उन्होंने अपने वाणिज्यिक हितों के विभिन्न मुद्दों का चयन करने का प्रस्ताव किया। जैसे-जैसे, सदस्य गैर-एलडीसी देशों के मसले लेकर आए, चर्चा अल्प विकसित देशों से संबंधित मसलों से दूर होती गई। अल्प विकसित मसलों में ये शामिल हैं (i) शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच (ii) डीएफक्यूएफ बाजार पहुंच बनाने के लिए उद्गम नियमावली (iii) सेवाओं में अल्प विकसित देशों को छूट (iv) सूती कपड़े से संबंधित मुद्दे (सूती कपड़ों और प्रशुल्क के लिए घरेलू और निर्यात सब्सिडियां)। 'एलडीसी प्लस' पैकेज के अलावा जिन कुछ मुद्दों पर सुझाव दिया गया था, वे थे-व्यापार को सुसाध्य बनाना और कृषि वार्ता के निर्यात प्रतिस्पर्धा स्तंभ। हालांकि शीघ्र परिणाम पैकेज के तत्वों पर सर्व-सम्मति होने में कोई प्रगति नहीं हुई। एलडीसी देशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि एलडीसी पैकेज दिसम्बर 2011 के मंत्रालयी सम्मेलन के समय नहीं दिया जाता तो वे बहुत निराश होंगे। अफ्रीकी समूह, अफ्रीका कैरिबियन-पेसिफिक समूह और विकासशील देशों के अन्य समूहों ने सम्मेलन में शीघ्र एलडीसी पैकेज के प्रयास का समर्थन किया। भारत ने भी इस कदम का समर्थन किया (बॉक्स 7.4)।

7.56 अक्टूबर-नवम्बर 2011 में डब्ल्यूटीओ के कुछ विकसित सदस्य देशों द्वारा संयुक्त प्रयास किए गए ताकि नवम्बर 2011 में जी-20 अग्रणी राष्ट्र के सम्मेलन का उपयोग करके दिसम्बर 2011 में जिनेवा में आयोजित किए जाने वाले आठवें डब्ल्यूटीओ मंत्रालयी सम्मेलन के लिए एजेण्डे को बढ़ाया जा सके। विशेष रूप से, वे डब्ल्यूटीओ वार्ताओं (बल्कि बहु-पक्षीय करार) में चुनिन्दा मसलों पर अनेकपक्षीय करारों के लिए मंच तैयार करना चाहते थे; वे डब्ल्यूटीओ सदस्यों से निर्यात प्रतिबन्धों के प्रयोग की आलोचना करने की प्रतिबद्धता पर सहमति लेना चाहते थे; और वार्ता के नए मसलों नामत: जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा पर वार्ता आरंभ करना चाहते थे। आठवें डब्ल्यूटीओ मंत्रालयी सम्मेलन से पहले के सप्ताहों में डब्ल्यूटीओ में खलबली देखी गई क्योंकि कुछ सदस्यों ने मंत्रालयी निर्णयों के लिए एजेण्डा में विभिन्न मसलों को शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन इन प्रस्तावों को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों का समर्थन नहीं मिला। 15 से 17 दिसम्बर को आयोजित आठवें मंत्रालयी सम्मेलन में मंत्रियों ने बौद्धिक सम्पदा (आईपी), इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य, लघु अर्थव्यवस्थाओं, एलडीसी की सहमति, एलडीसी के लिए सेवाओं संबंधी छूट और व्यापार नीति की समीक्षा पर कई निर्णय लिए। कई सदस्यों ने अनेक मुद्दों को लेकर बड़े संदेह व्यक्त किए। कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि कार्य के प्रति किसी भी प्रकार का अलग रुख दोहा अधिदेश के अनुरूप होना चाहिए, एकल उपक्रम का सम्मान किया जाए और यह सचमुच बहुपक्षीय, पारदर्शी और समावेशी हो। भावी कार्रवाइयों को देखते हुए कई मंत्रियों ने विकास

बॉक्स 7.4 : वार्ता के प्रमुख मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण: सारांश

कृषि

- अमरीका और यूरोपीय संघ के समग्र व्यापार-विकारजनक घरेलू सहायताा (ओटीडीएस) में पर्याप्त और प्रभावशाली कटौती;
- विशिष्ट उपादों (एसपी) की समुचित संख्या का स्वत: नामांकन;
- एक संचलनात्मक और प्रभावशाली विशेष सुरक्षा कवच तंत्र (एसएसएम);
- विकसित देशों के प्रशुल्कों का सरलीकरण और सीमांकन;

कृषि-भिन्न बाजार सुविधा (एनएएमए)

- आर्थिक रूप से कमजोर उद्योगों को बचाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लोचशीलता;
- क्षेत्रक कार्यकलाप में भागीदारी केवल गैर-अनिवार्य आधार पर और सद्भाव से की जाएगी एवं अंतिम परिणाम पर कोई पूर्वनिर्णय न लिया जाए तथा विकासशील देशों के लिए पर्याप्त विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधान किए जाएं।
- टैरिफ मुक्त बैरियर (एटीबी) के विषयगत प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार जिनमें पर्याप्त समर्थन हो जैसेकि क्षैतिज तंत्र।

सेवाएं

- संशोधित पेशकशों, खासतौर से मोड 1 (सीमापार आपूर्ति) और 4 (देशजात व्यक्तियों की आवाजाही) में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने की आवश्यकता।
- विकसित देशों द्वारा घरेलू विनियमों का उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यान्वयन।

नियमावली

- डंपिंग रोधी कार्रवाई के संबंध में अनुशासन को कड़ा बनाना (दोषी ठहराने के खण्ड को हटाने और कम शुल्क नियमावली पर जोर देना)
- मत्स्यपालन सब्सिडियों पर विकासशील देशों के लिए प्रभावशाली, विशेष और विभेदक व्यवहार।

बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार के पहलू (ट्रिप्स)

- पेटेन्ट आवेदनों के लिए विशिष्ट समापन मानदण्ड को शामिल करते हुए जैव-विविधता संबंधी समझौते तथा करार और ट्रिप्स के बीच स्पष्ट सम्पर्क स्थापित करना।
- शराब और मदिरा के अलावा भौगोलिक संकेत (जीआई) हेतु संरक्षण बढ़ाना।

के महत्व पर बल दिया। कई मंत्रियों ने कपास सहित एलडीसी के हितों के मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कई सदस्यों ने कृषि वार्ताओं के तीनों स्तंभों की महत्ता का उल्लेख किया। बहुत से मंत्रियों ने व्यापार सुसाध्यता, विशेष और विविध (एसएण्डडी) व्यवहार, एसएण्डडी निगरानी तंत्र और एनटीएम का भी उल्लेख किया। एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए सौ से भी अधिक विकासशील देशों जिनमें भारत, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, के गठबंधन ने सम्मेलन के दौरान बैठक की और घोषणा जारी की जिसमें विकास के एजेण्डा पर बल दिया गया। उन्होंने बहुपक्षीय सर्वसम्मतियों पर लिए गए निर्णयों के स्थान पर अनेकपक्षीय करारों की जमकर आलोचना की।

भारत की पांचवीं व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर)

7.57 पारदर्शिता को बढ़ावा देने और व्यापार नीतियों तथा इसके सदस्यों की परिपाटियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए डब्ल्यूटीओ के पास अपनी व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा के लिए एक तंत्र है। विश्व व्यापार में अपने हिस्से के आधार पर, प्रत्येक सदस्य देश की व्यापार नीति की निर्धारित आवधिक अन्तरालों पर डब्ल्यूटीओ द्वारा समीक्षा की जाती है। भारत की व्यापार नीति की समीक्षा चार वर्ष में एक बार की जाती है। व्यापार नीति की समीक्षा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों को समीक्षाधीन देश की नीति के विभिन्न पहलुओं और परिपाटियों को लेकर प्रश्न करने और चिन्ता व्यक्त करने का अवसर देती है। भारत की पांचवीं व्यापार नीति की समीक्षा डब्ल्यूटीओ में 14 और 16 सितम्बर को आयोजित की गई थी। बैठक से पहले, डब्ल्यूटीओ सचिवालय ने डब्ल्यूटीओ के 26 सदस्यों द्वारा उठाए गए 886 अग्रिम प्रश्नों के भारत के लिखित उत्तरों का संकलन परिचालित किया था। समीक्षा के दौरान अधिकतर सदस्यों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता की प्रशंसा की जो कोई संरक्षणवादी उपाय किए बिना वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभावों को सहजता से झेल सकी। अनेक सदस्यों ने सम्पोषणीय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी व्यापार नीति का प्रयोग करने के लिए भारत की सराहना की। सदस्यों ने दोहा दौर की वार्ताओं में भारत के सकारात्मक व्यवहार को भी नोट किया। कुछ सदस्यों खासतौर से अमरीका ने कई मामलों पर कतिपय चिन्ता व्यक्त की। ये मुद्दे हैं: प्रशुल्क और शुल्क, लाइसेंसिंग और प्रतिबन्ध, व्यापार रक्षा उपाय (डंपिग रोधी), एसपीएस एवं टीबीटी, सरकारी अधिप्राप्ति, निवेश और निर्यात तथा कृषि सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजनाएं और कृषि हेतु प्रशुल्क संरक्षण, सेवा और निवेश। उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं भारत के 16 सितम्बर 2011 के समापन विवरण (बॉक्स 7.5) में दी गई थीं।

बॉक्स 7.5 : पांचवीं व्यापार नीति समीक्षा: उठाए गए मुद्दे और भारत की प्रतिक्रिया

भारत की व्यापार व्यवस्था का खुलापन: भारत की व्यापार व्यवस्था के खुलेपन के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। जवाब में भारत ने बताया कि साल-दर-साल भारत के आयात निर्यातों से अधिक होते रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, देश का पण्य व्यापार घाटा विश्व के सर्वाधिक पण्य व्यापार घाटों में से एक है। भारत स्वयं ही कई वर्षों से अपने प्रशुल्क कम कर रहा है। सर्वाधिक अनुग्रह-प्राप्त देश (एमएफएन) के प्रशुल्क की सामान्य औसत दर 2006-07 के 15.1 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 12 प्रतिशत रह गई। समय के साथ-साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के प्रशुल्क की सामान्य औसत दरें कम हो गई हैं। भारत की 71 प्रतिशत प्रशुल्क श्रृंखला पर प्रशुल्क 5 और 10 प्रतिशत के दायरे में है।

कृषि उत्पादों पर भारत की आबद्ध और प्रयोज्य दरों के बीच अन्तर: कुछ सदस्यों ने कृषि उत्पादों पर भारत की आबद्ध और प्रयोज्य दरों के बीच व्याप्त बड़े अन्तर का उल्लेख किया। भारत का जवाब यह था कि यह बड़ा अन्तर भारत के स्थिर और निरंतर स्वायत्त प्रशुल्क उदारीकरण को प्रतिबिम्बित करता है। पिछली व्यापार नीति समीक्षा से अब तक 4 वर्षों में कुछ कृषि उत्पादों पर प्रशुल्कों को खाद्य मूल्यों में बनी भारी अस्थिरता को देखते हुए समायोजित किया जाना पड़ा। अधिकतर मामलों में, प्रशुल्क कम किए गए हैं और उन्हें वैसा ही रखा गया है। कुछ ही मामलों में प्रशुल्क दुबारा बढ़ाए गए, लेकिन उनके मूल स्तर से अधिक नहीं।

निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात संवर्धन योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे गए। यह स्पष्ट किया गया कि भारत की निर्यात संवर्धन योजनाएं शुल्क निरावेशन की परिकल्पना पर आधारित हैं और समान अवसर प्रदान कर रही है। इन योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति पर पूछे गए कई प्रश्नों पर भारत ने स्पष्ट किया कि 2007 में भारत की व्यापार नीति की पिछली समीक्षा से बाद की अवधि में एफडीआई नीति को और अधिक उदार और निवेश के अनुकूल बनाने के लिए लगातार बल दिया जा रहा है। एफडीआई संबंधी दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत, सरल बनाया गया और समेकित किया गया है ताकि विदेशी निवेशकों के लिए एकल पॉलिसी प्लेटफार्म मुहैया कराया जा सके। इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नागर विमानन जैसे कई नए क्षेत्र या तो विदेशी निवेश के लिए खोले गए या फिर उनका उदारीकरण किया गया। कारोबारी वातावरण को सरल और सुप्रवाही बनाने तथा व्यवसाय हेतु अनुकूल विनियमन तैयार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत की बौद्धिक संपदा (आईपी) संबंधी नीति और प्रवर्तन: भारत की बौद्धिक संपदा संबंधी नीतियों से संबंधित प्रश्नों पर, भारत ने उत्तर दिया कि आईपी संरक्षण और प्रवर्तन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कॉपीराईट और ट्रेडमार्क अधिनियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों से डिजिटल प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विशेषत: डिजिटल नेटवर्क पर संरक्षित सामग्री के प्रसार के संबंध में सुरक्षा बढ़ेगी। आईपीआर प्रणाली को मजबूत करने के लिए इनमें प्रशासनिक के साथ-साथ न्यायिक उपाय भी जोड़े गए हैं। इन कानूनों में आईपी सुरक्षा संबंधी उपबंधों में आगे सीमा संबंधी उपाय जोड़े गए ताकि कॉपीराईट चोरी और फर्जी ट्रेडमार्क से संबंधित वस्तुओं का आयात रोका जा सके। भारतीय सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा की गई दूसरी पहल है आईपीआर संरक्षा प्रणाली के लिए वेब आधारित ऑटोमेटिक रिकार्डेशन और टारगेटिंग के जरिए अधिकार धारकों द्वारा ऑन लाईन पंजीकरण करने की सुविधा।

सरकारी अधिप्राप्ति: इस विषय पर, भारत ने स्पष्ट किया कि उन्नत प्रौद्योगिकी वस्तुओं की अधिप्राप्ति और 50,000 अमरीकी डालर से अधिक मूल्य वाली निविदाएं आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बोलीकर्ताओं के लिए खुली हैं। ऐसे प्रमुख सुधार जो धन का मूल्य बढ़ाने से जुड़े घरेलू सरोकारों से किए गए हैं, कवरेज बढ़ाने, पारदर्शिता और कार्यक्षमता में सुधार लाने और बेहतर प्रवर्तन के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। पूरे देश और अधिप्राप्ति करने वाली सभी कंपनियों जिनमें सरकारी क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, के लिए प्रयोज्य बहु प्रयोजनकारी कानून पर विचार विमर्श चल रहा है।

सैनेटरी और फाइटो-सैनेटरी (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी अवरोध (टीबीटी) संबंधी उपाय

भारत के एसपीएस और टीबीटी संबंधी उपायों के संबंध में किए गए प्रश्न के उत्तर में भारत ने स्पष्ट किया कि भारत के विरुद्ध उठाई गई विशिष्ट व्यापार संबंधी चिंताओं का अधिकांशत: समाधान किया जा चुका है। विगत में अपनाए गए विनियमन वैज्ञानिक जोखिम के विश्लेषण पर आधारित रहे हैं।

निर्यात प्रतिबंध: भारत के निर्यात प्रतिबंधों के इस्तेमाल के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए थे। भारत का जवाब यह था कि घरेलू आपूर्ति प्रबंधन के प्रयोजनार्थ कुछ अवसरों पर निर्यात प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया गया है किन्तु ये केवल अस्थायी तौर पर किए गए हैं। चावल और गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को 2009 में अव्यवस्थित उत्पादन होने के कारण बढ़ाना पड़ा और फिर 2010 में देश में पड़े पिछले चालीस वर्षों में सबसे भयंकर सूखे के कारण बढ़ाना पड़ा था। तथापि, गेहूं और गैर-बासमती चावल का निर्यात अब पूरी तरह मुक्त है। बासमती चावल का निर्यात खुला है और हमेशा खुला रहा है। कपास के निर्यात पर प्रतिबंध पिछले वर्ष केवल थोड़ी सी अवधि के लिए लगाया गया था। सूती धागों का निर्यात पूरी तरह खोल दिया गया है। इसी तरह कपास भी निर्यात के लिए मुक्त है।

अन्य मुद्दे: सीमा शुल्क का मूल्यन, टैरिफ, और अन्य प्रभार, आंतरिक कराधान, आयात लाइसेंसीकरण तथा व्यापार संबंधी उपायों के प्रयोग के संबंध में सवाल उठाए गए थे। इसके जवाब में इस ओर ध्यान दिलाया गया था कि भारत पर व्यापार उपायों के प्रयोग में संरक्षणवादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यदि यह बात होती तो टैरिफ को आबद्ध दरों तक बढ़ाने के आसान रास्ते को इस्तेमाल किया गया होता; यह रास्ता नहीं अपनाया गया है। डंपिंग रोधी उपाय अनुचित व्यापार व्यवहार के विरूद्ध न्यायसम्मत साधन हैं। अन्वेषण एक उचित और पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं और कड़ी संवीक्षा के अध्यधीन होते हैं। भारत नियमानुसार सिर्फ कम से कम शुल्क लगाता है न कि पूरा डंपिंग मार्जिन रखता है जैसाकि कुछ डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि व्यापार संबंधी उपाय संरक्षणवादी साधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कई सदस्य भारी मात्रा में ध नी होने पर भी सब्सिडियों को अपनी व्यापार नीति का हिस्सा बनाते हैं, भारत ने एक भी सब्सिडी रोधी कार्रवाई नहीं की है। आज की तिथि में, केवल एक ही सुरक्षा शुल्क प्रवृत्त है। आर्थिक संकट के चलते वर्ष 2009 में सुरक्षा संबंधी अन्वेषणों के आवेदनों की बाढ़ आयी थी। कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए थे किन्तु 9 मामलों में अन्वेषणों को या खत्म किया गया था अथवा कोई भी सुरक्षा शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया गया था। केवल पांच मामलों में शुल्क लगाया गया था और इन मामलों को भी वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत ने सुरक्षा उपाय के तौर पर कभी भी मात्रात्मक प्रतिबंधों का सहारा नहीं लिया है। आयात लाइसेंसीकरण मुख्यत: मानव, पशु, पादप जीवन तथा पर्यावरण बचाने के आधार पर केवल कुछेक ही मदों को प्रभावित करता है। लाइसेंसीकरण की प्रणाली खुली और पारदर्शी है। लाइसेंस बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं। सभी संगत विनियमन सार्वजनिक सूचना के लिए उपलब्ध हैं और डीजीएफटी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

7.58 भारत ने हमेशा एक मुक्त, साम्यपूर्ण, स्पष्ट, भेदभाव रहित और नियम-आधारित अन्तरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आधार का काम करते हैं, भारत अपने व्यापार भागीदार देशों/ब्लाकों के साथ क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से लगा है ताकि इसके निर्यातों के लिए बाज़ारों में विविधता लाई जा सके और उनका विस्तार किया जा सके। मुख्य मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) से संबंधित कुछ हालिया घटनाक्रम इस प्रकार है:

- भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)

  भारत-जापान सीईपीए 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षरित किया गया और 1 अगस्त 2011 को प्रवृत्त हुआ। सीईपीए एकल उपक्रम है जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इस करार में 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार, अनेक प्रकार की सेवाएं, निवेश, आईपीआर, सीमाशुल्क और व्यापार संबंधी अनेक मुद्दे शामिल हैं। यह भारत का तीसरा सीईपीए (सिंगापुर और कोरिया के बाद) है और विकसित देश के साथ पहला सीईपीए है।

- भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

  भारत-मलेशिया सीईसीए 18 फरवरी 2011 को हस्ताक्षरित किया गया और यह 1 जुलाई 2011 को प्रवृत्त हुआ। यह एकल उपक्रम है जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। भारत-आसियान वस्तु-व्यापार करार जिसे भारत और मलेशिया के बीच जनवरी 2010 से कार्यान्वित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने वस्तुओं के संबंध में ''आसियान प्लस'' बाज़ार सुविधा की पेशकश की है।

- भारत-आसियान वस्तु-व्यापार करार

  भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी संरचना करार पर 8 अक्तूबर 2003 को हस्ताक्षर किए गए। भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार भारत और मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के संबंध में 1 जनवरी 2010 को; भारत और वियतनाम के संबंध में 1 जून 2010 को; भारत और म्यांमार के संबंध में 1 सितंबर 2010 को; भारत और इण्डोनेशिया के संबध में 1 अक्तूबर 2010 को भारत और ब्रूनेई के संबंध में 1 नवंबर 2010 को; भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी 2011 को, भारत और फिलीपीन्स के संबंध में 1 जून 2011 को; और भारत और कम्बोडिया के संबंध में 1 अगस्त 2011 को प्रवृत्त हुआ। सेवा-व्यापार और निवेश से संबंधित भारत-आसियान सीईसीए को लेकर वार्ता चल रही है।

- भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश करार वार्ताएं

  नई दिल्ली में 7 सितंबर 2005 को भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार एक उच्च स्तरीय व्यापार समूह (एचएलटीजी) गठित किया गया था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश करार हेतु वार्ता जून 2007 में शुरू हुई और अभी भी जारी है।

- भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) बीटीआईए (आईसलैंड, नार्वे, लेहटनश्टीन और स्विट्ज़रलैण्ड)

  ब्रुसेल्ज़ और नई दिल्ली में अब तक बारी-बारी से वार्ताओं के तेरह दौर आयोजित किए जा चुके हैं। तेरहवां दौर नई दिल्ली में 31 मार्च से 6 अप्रैल 2011 तक आयोजित किया गया था। वाणिज्य सचिव और यूरोपीय संघ के व्यापार महानिदेशक की बैठक 25 अक्तूबर 2011 को दिल्ली में आयोजित की गई। 5-6 दिसंबर 2011 के दौरान ब्रुसेल्ज़ में मुख्य वार्ताकार की बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों के अलावा, दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रक-विशिष्ट अन्तर-सत्र और डिजिटल वीडियो कान्फ्रेंस भी कई बार आयोजित की गई हैं। दोनों पक्षों ने इन वार्ताओं को अधिक सक्रिय बना दिया है ताकि वर्ष 2012 के आरंभ में इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। वार्ताओं में शामिल क्षेत्रों में हैं–वस्तु-व्यापार, एसपीएस और टीबीटी, सेवा-व्यापार, निवेश, आईपीआर और जीआई, उद्गम संबंधी नियम, प्रतिस्पर्धा नीति, सीमाशुल्क और व्यापार सुविधा-तंत्र, व्यापार रक्षा, विवाद निपटान, मध्यस्थता तंत्र, सरकारी अधिप्राप्ति और सम्पोषणीय विकास।

- भारत-कनाडा सीईपीए

  दोनों देशों ने वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों से जुड़े सीईपीए के लिए वार्ताएं शुरू करने पर सहमति ज़ाहिर की है। वार्ताओं के चार दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

- भारत-न्यूज़ीलैण्ड एफटीए/सीईसीए

  भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए/सीईसीए के अब तक सात दौर आयोजित किए जा चुके हैं और वार्ताएं जारी हैं।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया सीई*सीए*

  भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार करार निष्पादित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अप्रैल 2008 में एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) गठित किया गया था। जेएसजी की सिफारिशों के आधार पर, भारत और

ऑस्ट्रेलिया ऐसे सीईसीए हेतु वार्ता कर रहे हैं जिसमें वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार, निवेश और आईपीआर से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। अब तक वार्ताओं के दो दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

चुनौतियां और संभावनाएं

संभावनाएं

7.59 भारत का व्यापार क्षेत्र, जो 2011-12 के पूर्वार्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, की संभावनाएं वर्ष के उत्तरार्ध में मन्द पड़ गई प्रतीत होती हैं क्योंकि गहराता यूरो ज़ोन संकट, यूरो क्षेत्र से निकट संबंध वाले देशों की व्यापार संभावनाओं पर काली छाया बनकर मंडरा रहा है। हालांकि भारत यूरोपीय संघ और अमरीका पर निर्भरता कम करके अपने बाज़ारों को विविध बनाने में सफल रहा है, फिर भी भारत के निर्यातों में यूरोप का 19.5 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, भारत के कुछ व्यापार भागीदार यूरोप पर निर्भर हैं, और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। बाल्टिक ड्राई इन्डेक्स एक बार फिर से मुश्किल में पड़ गया है और गिरते हुए 3 फरवरी 2012 को अपने निम्नतम अंक 647 पर पहुंच गया, जो वर्ष 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान दर्ज 663 अंकों के पूर्ववर्ती निम्न स्तर से लगभग 20 अंक कम था। यहां इस क्षेत्र को दोहरी मार लगी है, क्योंकि यह न सिर्फ विश्व-व्यापार के कार्यकलापों में गिरावट दर्शाता है बल्कि इससे नौवहन सेवा क्षेत्र को भी झटका लगा है। हालांकि लौह अयस्क की चीनी फेहरिस्त में बढ़ोतरी और चीनी नव वर्ष के उपलक्ष्य में 23 जनवरी से 28 जनवरी 2012 तक अवकाश इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यूरो ज़ोन में साधारण मंदी व्याप्त होने का पूर्वानुमान एक अन्य कारण हो सकता है। यह सब निकट भविष्य में विश्व-व्यापार के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसका भारतीय व्यापार पर भी असर पड़ने की संभावना है। आयात संबंधी हालिया आंकड़े भी न सिर्फ यूरोपीय संघ के आयातों में ही बल्कि अन्य एशियाई देशों और चीन, हांगकांग और सिंगापुर जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के आयातों में भी गिरावट इंगित करते हैं। दिसंबर 2011 के आयात संबंधी आंकड़े कतई उत्साहवर्धक नहीं हैं। चीन और हांगकांग के विश्व भर से हुए आयात की वृद्धि दरें कम थीं, जबकि भारत से किए जाने वाले उनके आयात की वृद्धि दरें क्रमशः केवल 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत थीं। यह चीनी नव वर्ष के अवकाश को लेकर विशेष एकाकी घटना हो सकती है। संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के मामले में, दिसंबर 2011 में विश्व भर से किए गए आयात की वृद्धि दरें साधारण है, भारत से किए गए उनके आयात की वृद्धि दरें क्रमशः 23 प्रतिशत और 34 प्रतिशत पर उत्साहवर्धक हैं, भारत से किए गए सिंगापुर के आयातों की वृद्धि दर 138 प्रतिशत पर बहुत अधिक थी। हालांकि हमें आशावान रहना चाहिए और उभरती वैश्विक स्थिति का भारत पर पड़ने वाले व्यापार प्रभाव को देखने के लिए कुछ और प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आने वाले महीनों में निर्यातों में धीमी वृद्धि होने की संभावना है। दूसरी ओर, 8 दिसंबर 2011 तक की स्थिति के अनुसार, तेल की कीमतों के 100 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर बने रहने और सोने की कीमतों के 1745 अमरीकी डालर प्रति ट्रांय आउंस के ऊंचे स्तर पर बने रहने के चलते आयात वृद्धि सिर्फ कम ही हो सकती है। अरब वसंत के शीघ्र बाद ही पश्चिम एशियाई देशों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों को भी हिसाब में लिया जाना होगा क्योंकि 21.02.2012 की स्थिति के अनुसार तेल की कीमतों (ब्रेन्ट) में 119.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल के स्तर पर उछाल आना शुरू हो गया है।

7.60 सेवा-क्षेत्र की स्थिति भी कुछ भिन्न नहीं है। नौवहन सेवाएं सीधे ही पण्य व्यापार पर निर्भर करती हैं और जैसाकि बाल्टिक ड्राई इन्डेक्स ने इंगित किया है, वे इस समय अपने निम्नतम स्तर पर हैं, हालांकि यह अस्थायी स्थिति हो सकती है। सॉफ्टवेयर निर्यातों का प्रदर्शन मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरो क्षेत्र की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। जहां अमरीका का भारत के सॉफ्टवेयर निर्यातों में लगभग 60 प्रतिशत है, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। तथापि, जो देश इस समय संकट का सामना कर रहे हैं, उनके प्रति कोई विशेष जोखिम नहीं है। भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के लिए उसी हद तक कारोबार का कोई अधिक नुकसान भी नहीं है। फिर भी, सॉफ्टवेयर निर्यातों में कुछ मन्दी देखी जा सकती है। यूरो ज़ोन भारत में पर्यटकों के कुल आगम का लगभग 30 प्रतिशत है और यूरो ज़ोन से विशेषकर प्रभावित देशों से पर्यटकों के आगमन में कमी होने के कारण यात्रा-निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। कारोबारी सेवाओं (जिनमें अनेक सेवाएं शामिल हैं) के निर्यात आम तौर पर कम स्थिर होते हैं क्योंकि यह क्षेत्र विदेशों में कारोबारी स्थितियों की अनिश्चितता पर निर्भर करता है। वैश्विक आर्थिक संकट के बाद उनमें 2009-10 में तेज़ी से गिरावट हुई और इस वर्ष (2011-12) के पूर्वार्ध में उनमें कमी हो चुकी है। इस स्थिति के बेहतर होने के कोई आसार नहीं हैं। परिणामतः, यदि अमरीका और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाएं पस्त ही बनी रहीं तो वर्ष 2009-10 की ही तरह, सेवा-निर्यात का अधिशेष 2011-12 की अंतिम दो तिमाहियों में सिकुड़ सकता है। सेवाओं के आयात की वृद्धि में गिरावट का रुख कम लोचशील प्रतीत हो रहा है जैसाकि 2008 के वैश्विक संकट में देखा गया था। लेकिन 2011-12 के पूर्वार्ध में यह केवल 1 प्रतिशत था। इसलिए, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों की गिरती वृद्धि दरों के साथ-साथ वस्तु एवं सेवाओं के आयात की वृद्धि दरों में कमी वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार-शेष पर दबाव डालती है; जब अप्रैल-जनवरी 2011में सीमाशुल्क आधार पर पण्य व्यापार घाटा 148.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अब तक का सर्वाधि

क था–यह ऐसी घटना है जो 2008 के वैश्विक संकट के दौरान या उसके बाद भी नहीं देखी गई थी।

चुनौतियां

7.61 व्यापार के मोर्चे पर भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां तो मौजूदा उभरती वैश्विक स्थिति के कारण और कुछ व्यवस्थागत एवं दीर्घावधिक स्वरूप की हैं। यदि वैश्विक स्थिति बिगड़ती है तो प्रोत्साहन उपायों के लिए दबाव पुनः उभरेगा और व्यापार भागीदारों द्वारा किए जाने वाले संरक्षणवादी उपायों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अमरीका द्वारा डम्पिंग-रोधी कार्रवाई में तेजी और यूनाइटेड किंगडम में वीज़ा संबंधी प्रतिबंधों पर तथा अमरीका में आऊटसोर्सिंग पर भाषणबाज़ी के चलते संरक्षणवादी उपायों का समर्थन ज़ोर पकड़ रहा है। हालांकि घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति को पहले ही काबू में लाया जा चुका है और पण्य आयातों पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तक बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण ऊंची मज़दूरी के साथ-साथ भारत में रोज़गार के अधिक अवसरों के सृजन से कम कुशल नौकरियों के लिए भारत और खाड़ी के देशों में मज़दूरी संबंधी अन्तर कम हो सकता है जिससे कामगारों के आवक विप्रेषण में क्रमिक कमी हो सकती है।

7.62 मध्यावधिक और दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। जहां भारत को एशिया और आसियान को किए जाने वाले निर्यातों के विविधीकरण के कारण संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों में व्याप्त स्थिति के संदर्भ में कम जोखिम है, वहीं चीन और स्विटज़रलैण्ड जैसे देशों के साथ भारत के उच्च और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर द्विपक्षीय व्यापार घाटे के मोर्चे पर चिन्ता बढ़ गई है। भारत के निर्यात-वस्तु समूह के विविधीकरण के मोर्चे पर बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि विश्व व्यापार की शीर्ष मदों के संबंध में इसके निर्यातों की उपस्थिति बहुत कम है। भारत ने जहां सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी), रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरी वस्तुओं जैसी कुशल और पूंजी प्रधान निर्यातों में नई शुरूआत की है, वहीं यह वस्त्रोद्योग, चमड़े और चमड़े के विनिर्माण, हस्तशिल्प और कालीन जैसे श्रम-प्रधान निर्यातों में अपनी परम्परागत शक्ति गंवाता जा रहा है। अवसंरचना संबंधी अड़चनों के अलावा प्रक्रियात्मक और प्रलेखन संबंधी कारणों से होने वाली देरी और अधिक लागत की स्थिति समाप्त करके व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना एक और बड़ी चुनौती है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के प्रकाशन ''डूइंग बिज़नेस 2012'' के अनुसार कारोबार करने में आसानी के मोर्चे पर भारत का 132वां रैंक है। सिंगापुर तो पहले स्थान पर है ही, वहीं श्रीलंका, वियतनाम, पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देश भी भारत से आगे हैं। ''सीमावर्ती व्यापार'' को लेकर भारत का दर्जा 109वां है जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर और चीन 60वें स्थान पर है। भारत में स्वीकृति हेतु 8 निर्यात दस्तावेज़ हैं और चीन के 5, जबकि फ्रांस जैसी उत्कृष्ट प्रथाओं वाली अर्थव्यवस्थाओं के 2 दस्तावेज़ हैं। भारत के संबंध में निर्यात के लिए लगने वाला समय 16 दिन है, चीन के लिए 21 और डेनमार्क के लिए 5 दिन हैं। निर्यात की लागत 1095 अमरीकी डालर प्रति कन्टेनर है जबकि चीन में यह लागत 500 अमरीकी डालर और मलेशिया में 450 अमरीकी डालर है। स्वीकृति प्राप्ति के आयात दस्तावेजों की संख्या भारत में 9, चीन में 5 और फ्रांस में 2 है। आयात में लगने वाला समय भारत में 20 दिन, चीन में 24 दिन और सिंगापुर में 4 दिन है। आयात की लागत भारत में 1070 अमरीकी डालर प्रति कन्टेनर, चीन में 545 अमरीकी डालर और सिंगापुर में 439 अमरीकी डालर है। इस प्रकार व्यापार सरलीकरण के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना है। हालांकि भारत ने सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में काफी हद तक स्थिरता हासिल कर ली है, लेकिन कारोबारी सेवाओं के निर्यात में स्थिरता अभी कम है। पर्यटन सेवाओं के निर्यात की संभावनाओं में भारत में चल रही भाषणबाजी के बावजूद, वास्तविक परिणामों में और सुधार हो सकता है। अन्ततः हालांकि विश्व व्यापार संगठन के साथ चल रही वार्ताओं के निकट भविष्य में सार्थक निष्कर्ष निकलने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, फिर भी भारत द्वारा क्षेत्रीय द्विपक्षीय करारों की दिशा में आगे बढ़ने से सार्थक और परिणामोन्मुखी मुक्त व्यापार करार और व्यापक आर्थिक सहयोग करार निष्पादित होने चाहिए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि व्यापार के मोर्चे पर भारत के सामने खड़ी चुनौतियां कठिन अवश्य हैं लेकिन उनका समाधान तेज़ी और कुशलता से किया जाना चाहिए क्योंकि मौजूद अवसर अपार हैं और अभी तक उनसे फायदा भी नहीं उठाया गया है।